हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

12 फरवरी, 2004

खण्ड–1 अंक–5

अधिकृत विवरण

विशय सूची

वीरवार, 12 फरवरी, 2004

	पृश्ठ संख्या
तारांकित प्र न एवं उत्तर	1
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	19
अतारांकित प्र नों एवं उत्तर	21
निलम्बित सदस्यों श्री रघुबीर सिह कादियान तथा श्री जयप्रका ा बरवाला को वापिस बुलाने के लिए अनुरोध करना	24
ध्यानकर्शण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्तावों सूचना	24
वर्श 2004–2005 के बजट अनुमार प्रस्तुत करना	25

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 12 फरवरी, 2004

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबरी सिह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः मैम्बर माननीय सदस्यगण, अब प्र नकाल होगा।

Allotment of Agencies by HAFED

1670 Sh. Rambir Singh: Will the Minister for co-operation be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to allot Agencies by the HAFED for selling products at District Headquarters and Tehsil Headquarters?

सकरित मंत्री (श्री करतार सिंह भडाना): नही, श्रीमान जी। हालांकि हैफेड अपने उत्पादों की बिक्री के लिए ग्रामीण स्तर पर फ्रैन्चाईजिज नियुक्त करने के लिए कदम उठा रही है।

श्री रामबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्य से सहकारिता मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह मामला बेरोजगारी से सम्बन्ध रखता है मै जानना चाहूंगा कि क्या

बेरोजागार लोगों को हैफैड की एजेसीज जिला स्तर पर, और ब्लॉक स्तर पर दी जाएंगी ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। अध्यक्ष होदय, हैफेड एक कमर्ियल संसगि है जो अच्छे–अच्छे प्रोडैक्ट बनात ीळै अगर ऐसा कदम उठाया जाता है तो उन प्रोडैक्ट को बेचने में भी आसानी होगी। क्या मंत्री महोदय इस पर पुनविचार करेगे?

श्री करतार सिंह भडानाः स्पीकर सर, सरकार का हैफेड की एजेसीज गांव लैवल पर देने का विचार हैं हैफेड के पास इस प्राकर की एजेंसीयज लोने के लिए 300–350 एप्लीकें ांज आई थी। जिन मेंसे 154 व्यक्तियों को एजेसीज का लईसेंस दे दिया गया है मै सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि यह सरकार चौधरी देवी लाल जी के बताये हुए रास्तें परचलने वाल सरकार है। और उसी रास्तें पर यह मौजूदा सरकार चल रहीहै ओर इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमनें ये एजेंसीज दी है ताकि सभी लैवल परलोगों को रेाजगार मिल सके। गांव लैवल परयदि कोई और व्यक्ति भीा हैफेड की एजेीसज लेना चाहेगा तोउसको भी दे दी जायेगी। जिला लैवल पर भी ऐसी एजेसीज देने के लिए हम विचार कर रहे है।

श्री पूर्ण सिंह डाबड़ाः स्पीकर सर, मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हैफैड को जो प्रोफिट होता है उनको वह इन भागीदारां में भोयर करती है या खुद आपने पास रख लेती है।

श्री करतार हसंह भडाना: अध्यक्ष महोदय, मै सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हैफेट प्रोफिट का 5 प्रति ात भोयर पास रखती है औरबाकी का प्रोफिट सोसायटी का दे देती है।

श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा: अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के हिसाब से हैफेड मेजन भोयर अपने पा रखती है। जबकि मिनी बैंक तक जो भोयर जाना चाहिए वह नही जा पाता। मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस विशय में सरकार पुनः विचार करके इसका सरलीकरण करने परविचार करेगी?

श्री करतान सिह भडाना: अध्यक्ष महोदय, सरकार की सोच है कि गांव में एजेंसी दे दिए जाने के बाद गांव में हैफेड प्रोडैक्ट को खुद पहंचाने का साधन मिल जायेगा और बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसमें हैफेड को प्रोफिट की कोई जरूरत नही है। यह देने चौधरी दर्वी लाल जी की दी हुई है ओर उसी परसरकार अमल कर रहीहै। इस संस्था का प्रौफिट कमाने का अपना ध्येय नही है, इसका ध्येय सिर्फ रोजगार देना है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी आप बताएं कि जोग ांव में लोगों को एजेसीज देने जा रहे है उनमें कौन कौनसे प्रोडैक्ट रखने का लाईसेस देगे?

श्री करतार सिह भडाना: अध्यक्ष महोदय, फिलहान तो खाद ही देने का मेन काम है।

श्री अध्यक्षः खाद के अलावा हैफेड के बहुत सारे प्रोडैक्टस जैसे तेल, घी, चावल आदि भी है। आप बताएं कि क्या खाद की ही एजेंसीज देगे या इन दूसरें प्रोडैक्टस को भी रखने की इजाजत देगे।

श्री करतान सिंह भडानाः दूसरे प्रोडैक्टस को भी देने का मामला विचारधीन है, इसकी हम कोि ा ा करेगे।

तारांकित प्र न संख्या 1693

(यह सवाल पूछा नही गया क्योकि इस समय माननीयसदस्य श्री तेजवीर सिंह सदन में उपस्थित नही थे।)

Re-Starting of Diploma in Modern Office Practice

1743 Sh. Padam Singh Dahiya: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) Whether it is a fact that the Diploma Course in Modern Office Practice in Government Polytechnic College Sonepat has been stopped; if so, the reasons thereof; and

(b) Whether the Course, as referred to in part (a) above is likely to be restarted again; if so, the time by which it is likely to be re-started?

मुख्य संसदीयसचिव (श्री राम पाल माजरा):

(क) श्रीमान जी, राजकीय बहुतकनीकी, सोनीपत में मार्डर आफिस प्रैक्टिस का डिप्लोमा कोर्स कभी भी आरम्भ नही हुआ अतः इसे बंद करने का प्र न ही उठता।

(ख) आव यक आधारभूत सुविधाएं सुविधाएं उपलब्ध कराने के उपरांत सत्र 2005–06 से इस कोर्स के आरम्भ करने बारे में सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

श्री पदम सिंह दहियाः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय सी0 पी0 एस0 महोदय से यह जानना चाहूगा कि मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिसका डिप्लोमा करवाना बन्द कर दिया गया है यदि हां, तो इस डिप्लोमा को फिर से भाुरू करवाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है, यदि हां, तो इसे कब से भाुरू किया जाएगा?

श्री राम पाल माजराः स्पीकर सर, मॉडर्न आफिस प्रैक्टिस के कोर्स के बारे में इन्होने पूछना चाहा है और यह भी जाननाचाहा कि इस कोर्स को कब से भाुरू करने जा रहे है तो मै इनको बताना चाहूंगा कि इसकोर्स के प्रति छात्रों में कोई रूझाननही है और यह कोर्स जॉब ओरिऐंटिड भी नही है। इस कोर्स में कुछ रिफोर्म करके इसको ऑफिस मैनेजमैंट एण्ड कम्पयूटर ऐप्लीके ान कोर्स करने का प्रस्ताव है ताकि इसमें कम्पयूटरऐड हो जाने से यह जोब ओरिऐंटिड कोर्स हो जाए। इस कोर्स के बारे में पहले भी कुछ ऐसी स्थिति रही है कि जहां पर

भी यह कोर्स चलाया गया वहां परकक्षा मेंपूरे छात्र नही पाए। जैसे कल्पना चावला राजकीय महिला बहुतकनीकी संस्थान, उतावड़ में है, बी0 बी0 एसण बहुतकनीकी कन्या गुरूकुल, खानपुर में और वै य बहुतकनीकी संस्थान में 44सीटें थी और 41 छात्रों ने वहां पर दाखिला लिया। 2003–04 में 44 सीटे इनटैंक की थी और उसमें 19 छात्रों ने दाखिला लिया। 2003–04 में 44 सीटे थी और 36 छात्रों ने दाखिला लिया था। स्पीकरसर, छात्रों में इस डिप्लोमा के प्रति रूझान नही है इसलिए हमने इसकोर्स को भुारू नही किया है। इसमं कुछ रिफार्म करके ऑफिस मैनजमैंट एण्ड कम्पयूटर ऐप्लीके ान कोर्स करने का विचार हैं जहां तक मेरेसथी ने कहा है कि इस कोर्स को बन्द करने का विचार है तो इसे बन्द नही किया गया है। कोर्सो के बारेम ें जो स्थिति है जै उसके बारे में हाउस को थोडा बताना चाहूंगा। हमारे जो टैक्नीकल कोर्सिज गुरू जम्भे वर यूनिवर्सिटी, हिसार से होते है उनकी जुलाई, 1999 से स्थिति इस प्रकार है कि इसमें इनटैंक की 650 सीटें थी इन्हे बढ़ा कर 990 किया गया हैजो कि 52 प्रति ात वृद्धि है। इसी प्रकार से इन्जीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 20 से बढ़ा कर 34 कर दी गई है जो कि आपने आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एम0 टैक के लिए 141 सीटें थी जिन्हे बढ़ाकर 226 कर दिया गया है यानि इसमें 60 प्रति ात की वृद्धि हुई है। स्पीकरसर एम0बी0ए0 के कोसिर्ज केवल दो कालिजिज में थे अब उनको 28 कालिजिज में कर दिय गया है और उनकी इनटैक सीटें 90 थी जिनको बढ़ा कर 1525 कर दिया गया है यादिन 160 प्रति ात सीटों की वृद्धि की

गई है। होटल मैनेजमैंट एण्ड केटरिंग टैक्नोलोजी का कोर्स 60 सीटों से भ्रारू किया गया है इसी प्रकार से फार्मेसी कॉलेज दो थे वे बढ़ाकर 7 कर दिए गए है, इसमें 80 सीटें थी जिन्हें बढ़ाकर 370 कर दिया गयाहै जो यानि 362 प्रति ात की वृद्धि की गई है। पोलिटैक्निक संस्थान 25 थे वे बढ़ा कर 31 कर दिए गए है और इनमें 3945 सीटें थी जिन्हें बढ़ाकर 6310 कर दिया गया यानि 60 प्रति ात की वृद्धि की गई है। स्पीकर सर, मेरे कहने का भाव यह था कि पॉलिटैक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 58 थी जो बढ़कर 117 हो गई है और इनमें सीटों की संख्या 9308 थी उन्हें बढ़ा कर 20970 कर दिया गया है जा कि अपने आप में एक रिकार्ड है।

श्री अध्यक्षः ये फिगर्ज कब से कब तक के है?

श्री रामपाल माजराः स्पीकर सर, जुलाई 1999 से 2003–04 तक के आंकड़ों का मैने कम्पैरीजन किया है।

श्री गोपी चन्द गहलोतः अध्यक्ष महोदय, मै सदन यह बतानाचहूंगा कि मेरी कांस्टीच्युएंसी गुडगांव में इंडस्ट्रीलाईज ान की दृश्टि से जो काम हुए है वह एक रिकार्ड है उसक दृश्टिगत आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गुडगांव मे घोशणा की थी कि गुडगांव में एक पोलिटैक्नीक कालेज खोला जाएगा। लेकिन उनकी घोशण किसी ने किसीवजह से लेट रहीह। अयक्ष महोदय, आज गुडगांव में सब कुछ मिल जात है लेकिन वहां पर जमीन नही मिलती है। वहां

की पंचायत उसके लिए पैसा लगाने के लिए भी तैयार है मेराआपसेनिवेद है कि यह जो इंस्टीच्यूट के लिए जमीन नही मिल रही है तो क्या हुड्डा को इसके लिए रियायती दरों पर जमीन देनी चाहिए या नही देनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्र न है कि गुडगांव में हमने बड़े एफर्टस करके जॉब ओरियंटिड कोर्स भाुरू करवाया थ। हरट्रोन के माध्यम से बड़ी मु कल से स्टैनोग्राफी का कोर्स भाुरू किया गया था लेकिनसुनने में आया है कि वाहं से हरट्रोन ि ाफ्ट हो रही है। अध्क्ष महोदय, मंत्री जी यह बताए कि क्या वहां से हरट्रोन को ि ाफ्ट कर रहे है। अगर कर रहे है तेा कब कर रहे है। गर नही कर रहे है तेा क्या वहां पर वह स्टैनोग्राफरी का कोर्स जारी रहेगा।

श्री रामपाल माजराः अध्यक्ष महोदय, गुडगांव में पोलिटैक्नीक कॉलज खोलन`की बात की गई है तो इसके लिए एक क्राईटेरिया है कि अगरकही भ्झी इस किस्म का कालेज खोलना होता तो वहा पर 10 एकड़ जमीन हीन चहिाए। लेकिन ये कह रहे हैथ क गुडगांव में जमीन मिलना मु कल है। अध्यक्ष महोदय, अगर आज भी कोई एप्लके ान देता है तो इसके पहले ए0आई0सी0टी0ई0 की परमि ान लेनी पड़ती है। अग इसकी स्टेट को अथौराईजे ान दे दी है। अगर स्टेट परमि ान देती है तो ए0आई0सी0टी0ई0 को रैफर कर दिया जाता है। जहां तक मुख्यमंत्री जी ने घोशणा की बात है तो मुख्यमंत्री जी ने जो भी घोशणाएं की है उनको पूरा किया जाएगा। जहां तक गुडगांव में

जमीन की बात है, तो जमीन वहां पर नही मिलती है इस बारे मे माननीय गहलोत जी ने भी बताया है। अध्यक्ष महोदय, बिना जमीन के कोई भी इंस्टीच्यूट नही खोला जा सकता है। जहां तक पोलिटैक्नीक इंस्टीच्यूट की बात है। तो इस बारे में हम विचार करेगे।

चौधरी नफे सिंह राठीः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जाननाचाहूंगा कि हरियाणा में वैसे तो बहुत ही विकास कार्य हुए है और इस सकरार ने 39000 नौजवानों को नौकरियां प्रदान की है लेकिन बेरोजगारी की समस्या परपूरी तरह से काबू नही पाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, जो युवा डिप्लोमा या डिग्री लेकर निकलते है, क्या उनको हरियाणाकी प्राईवेट फर्मो में नौकरी की सुविधा प्रदान की जाएगी?

श्री रामपाल माजराः अध्यक्ष महोदय, जो भी युवा इंजिनियरिंग कालेजों से और पोलिटैक्नीज संस्थाओं से जॉब आरियांटिड कोर्स करके निकलते है, उकनी रिक्वीजि ान प्राइवेट फर्मो को भेज दी जाती है ओर वे फर्म उन युवाओं को नौकरी पर लगाते भी है। लेकिन यह बॉय लाज कम्पलसरी नही किया जा सकता है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हरट्रोन का क्या फेट है?

हरट्रोन ने ऐ कितने विद्यार्थी तैयार किया है जिनका जॉब मिली है।

श्रीरामपाल माजराः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से हुड्डा जी को बताना चाहूंगा कि इनके सवाल का तारांकित प्र न से कोई सम्बन्ध नही हैं अगर ये इस बारे में जानकारी चाहतो है तो अपना सवाल अलग से लिखकर भेज दें।

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, इस सरकार ने आते ही यहनीति बनायी थी कि युवाओं को प्रोफे ानल और स्पे ालाईज ऐजुके ानदी जाएगी। क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है कि आप केवल यह नही सोच सकते कि सरकारी नौकरियों से आप बेरोजगारी दूर कर सकते है बेरोजगारी तभी दूरी हो सकती है जब आप युवओं को प्रोफे ालन ऐजुके ान दें ताकि इस तरह की एजेके ान प्राप्त करके व अपना स्वयं कारोजगार भुरू कर सकें। चाहे वे किसी प्राईवेट कम्पनी में लगें या सरकारी नौकरी में लगे लेनि प्रोफे ानल ऐजुके ान लेने के बाद उनक लिए सब जगहों पर नौकरी के दवाजे खुल जो है, पूरा वर्ल्ड उनके लिए ओपन हो जाता है। पूरी दुनिया खुल जाती है। और अगर यहां का बच्चा प्रोफे ानली अच्छाहोगा तो यह भी हो सकता है कि उसको इंग्लैण्ड या अमरीका में अच्छी नौकरी मिल सकती हैं स्पीकरसर, हमारी इंस्टीच्यू ान आई0टी0आई0ज0, पोलिटैक्निक कालेजिज में ये इंजीनियरिंग कालेजिज में ही दी जाती थी औरवह ट्रेडी ानल ऐजुके ान चली आ रही थी मोटर

मैकनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, फलाना मैकेनिक या फिटर आदि कई इस तरह की ट्रेड चली आ रही थी। मोटर्ज की ट्रैनिंग, फलाना मैकेनिक या फिटर आदि कई इस तरह की ट्रेड चली आ रही थी। मोटर्ज की टैनिंग आई0टी0आईज0 के बजाए बाहर वर्क ाप में ढ़िया मलती थी। इसलिए इनकी तरफ रूझान खत्म हो गया था। परन्तु अब सरकार ने इन्हें अपडेट करने के लिए इस दि ा में कदम उठज्ञए है। अब इंडस्ट्रीज के साथ टैक्नीकल डिपार्टमैंट का टायअप रहता है कि किस एरिया में किस किस्म की इंडस्ट्री आ रही है। और किस किस्म की इनको मैन पाव चाहिए। वे एक विजन रखते है। आप केवल हिन्दुस्तान ही नही बल्कि कोई भी दे ा अकेला नही रहा सकता सारी दुनिया के साथ आज मुकाबला है। आज बर्ल्ड कम्पिटी ान हो रहा है ईवन मैन पावर कर रही है। इसी बात को देखकर जैसा कि अभी सी0 पी0 ए0 साहब ने बताया कि हरियाणा में चाहे वह टैक्नीकल या पोलटैक्निक लेवर पर हो, चाहेवआ आई0टी0आई0 लेवर पर हो या चाहे वह दूसरे प्रोफे ानल कोर्सिज हों, सामायिक प्रोफे ानल कोर्सिज खोले जा रहे है। चाहे उनको दो साल के लिए बंद करकेतीसरे कोर्स भुरू करने पड़े `किन समय के हिसाब से कोर्स खोलने जा रहे है। क्योंकि अकेला ट्रेडी ानल कोर्स काम नही आएगा, काम वही आएगा जिस किस्म की इंडस्ट्रीज को मैन पावर चाहिए। इसलिए इसकी तरफ हमारा पूरा ध्यान है। हुड्डा साहब ने जैसे हरट्रोन का जिक्र कियाथा। हरट्रोन नेभी जितनी दूसरी प्राइवेट कम्पनीज है उनके साथ कम्पीट किया है। जिला हैड क्वार्टर पर या सब

डिवीजन हैड क्वार्टर पर भी काफी फ्रैन्चाइज उसने दी है ताकि इनकी क्वालिटी अच्छी रहे और लोग वहां से प्राफे ानल ऐजुके ान प्राप्त करके मार्किट में आये। यह बात ठीक है अगर इस बारे में स्पैसिफिक आंकडे होत तो दिए जा सकते थे लेनि यह सही है कि जो निट या एप्टैक बगैरा दूसरी संस्थाएं है उनसे भी बढ़िया काम हरट्रोन कर रहाहै।। निट या एप्टैक की तरफ जाने के बजाए हरट्रोन की फ्रैन्चाइज की तरफ लोग दौड़ रहे है ताकि हरियाणा क लिए गौरव की बात है। हरट्रोन ने बहुत बढ़िया प्रोफे ानल काम किया है।

श्री गोपी चन्द्र गहलोतः माननीय स्पीकर साहब, सम्पत सिंह जी ने और नफे सिंह जी ने जी जॉब ओरियन्टेड कोर्सिज के बारे में अभी कहा। मेरा आपसे अनुरोध है, अनुरोध ही नही बल्कि मैं आपसे गुजारि ा करूंगा कि जिस तरफ से इंडस्ट्रीज गुडगांव हमें खासकर आ रही है और जो इनमें स्थानीय लोगों को जॉब देने की बात बार–बार उठ रही है तो उसके दृश्टिगत वहां पर जॉब ओरियएन्टेड कोर्सिज लेटैस्ट भुरू करवाए जाएं। स्पीकरसाहब,वहां पर पहले डुंडाहेड़ा, मोलाहेड़ा या सिंहरोल गांव के जिन लेागों की जमीन इंडस्ट्रीज में गयी थी उनको नौकरी दिलवाने के लिए एक बड़ा आंदोलन किया गया था, स्थानीय युवकों को रोजगार दिलवाने के लिए ऐजीटे ान करके गेट पर गिरफ्तारियां दी गयी थी जब जाकर इंडस्ट्री वालेां ने कुछ स्थानीय लोगों को अपने यहां नौकरियों पर रखा था। लेकिन मैं बड़े खेद

के साथ कहना चाहूंगा कि अब वहां पर मारूति में वी0आर0एस0 के नेता सी0आर0एस0 भ्रुरू हो गयी है और मारूति के अंदर से वी0आर0एस0 की आंड में काफी स्थनीय लोग नौकरी से निकाले गये है। इन निकाले हुए लड़कों मेंज्यादातर लड़के उन गांवों के है जिनकी जमीन जाने के बदले में उनको नौकरी दी गयी थी। तो इस बारे में मै जानना चाहूंगा कि सरकार क्या कदम उठा रही है?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ने ठीक कहा कि पहले कम्पीन के अंदर धारणा यही थी कि लोकन टैलेंटस को वे इग्नोर करत`थे क्यों वे सोचते थे कि लोकल टैलेंटस स्ट्राइक हुर्ठ थी तो वह बाहर के टैलेंटस की वजह से नही बल्कि लेाकल टैलेटस की वजह से ही बची थी। इसलिए अब यह कम्पनीयज भी जान गयी है ि इनको लोकर टैलेंटस को भी लेना पड़ेगा। स्पीकर सर, सरकार तो इन पर अपनाप्रभाव ही डाल सकती है। हमारे जो इंडस्ट्रीज या दूसरे डिपर्टमैंटस है वे इनके साथ्ज्ञल लायजन रखते है। ये जो इस तरफ से वी0आर0एस0 या दूसरी तीसरी स्कीम्ज लागू कर रहे है तो इसमें प्रयास यही रहेगा कि हरियाणाके जो बच्चे उनमें लगे हुए है उनको वे न निकालें। हम सिर्फ प्रयास यही रहेगा कि हरियाणा के जो बच्चे उनमें लगे हुए है उनको वे न निकालें। हम सिर्फ प्रयास यही रहेगा कि हरियाणा के बच्चे उनमें लगे हुए है उनको वे न निकाललें। हम सिर्फ प्रयास रहेगा कि उसमें जो नॉन–टैक्नीकल और टैक्नीकल लोग प्रदे ा में उपलब्ध है उनकी मेरिट बनती है

उसमे ंवरीयता हरियाणा प्रदे ा के बच्चों को ही दी जाएगी। यह हरियाणा सरकार की तरफ सेपूरा प्रयास रहेगा। यह मैं पूरे हाउस को सरकार की तरफ से कमिटमैंट करता हूं।

Introduction of Sector System in Villages

1733. Sh. Bhagi Ram: Will the Minister for Town and Country Planning be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to intorduce system in villages on the pattern of HUDA; if so, the detail theroof?

नगर एवं ग्राम आयोजन मंत्री (श्री धीरपाल सिह): माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि भाहर की तरह गांव के लोगों को भी सुविधा मिले उन्ही नीतियों पर चलतेहुए विभाग ने कुछ कदम उठाए है मैं उन पर प्रका ा डालने जा रहा हूं–

राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक विकास खंड़ से कम से कम एक गांव को एक छोटा रिहाय ी सैक्टर स्थापित करने के लिए, चुनने का निर्णय लिया है। लेकिन प्रथम चरण में, इस योजना के क्रियान्वित करने के लिए, प्रत्येक जिले में से एक गांव चुना जा रहा है। योजना का विवरण इस प्रकार है:–

1. ग्राम पंचायत रिहाय ी क्षेत्र विकसित करने के लिए कीमत पर भूमि उपलब्ध कराएगी।

2. इसके लिए न्यूनतम 10 एकड़ भूमि की आव यकता होती है।

3. प्लाट धारक परकोई परीक्षण भाुल्क और परिवर्तन भाुल्क नही लगाया जाएगा।

4. भवन मानचित्र संबंधित पंचायत द्वरा स्वीकृत की जाएगी।

5. पक्की सड़के, जल वितरण, सीवर/नालियां, विद्युतिकरण और सड़कों पर बिजली की व्यवस्था, सड़कों को साथ पौध रोपण और पार्क आदि सुविधाएं दी जाएंगी।

6. जिस गांव में सामुदायिक केन्द्र/पंचायतघर की सुविधा नही है, वहां इनका भी निर्माण किया जाएगा।

7. क्षेत्र में एक छोटा वाणिज्यिक केन्द्र विकसित किया जाएगा।

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से जो देवी रक्षक स्कीम है। मया जो कन्यादान स्कीम थी उसमें हरि गरीब आदमी जो बी0पी0एल0 के तहत आते है अब उनको इसके साथ जोड़ा गया है। मै जानना चाहूंगा कि यह जो हुड्डा के प्लॉट कोटे जाएंगे उसमें भी क्या उन लोगों को भामिल किया जाएगा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग है। यदि उनको भाामिल किया जाऐगा तो क्या उनसे भूमि की पूरी कीमत वसूली जाएगी या उसमें कुछ रियायत दी जाएगी, क्या सरकार का इस स्कीम में ऐसा कोई प्रावधान है?

श्री धीरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्दे ा दिए कि जिस भी गांव की पंचायत की जमीन पर रिहाय ी सैक्टर विकसित किया जाएगा उस जमीन को फ्री कॉस्ट न लेकर कीमत के आधार पर लिया जायेगा। पंचायत को भूमि की कीमत अदा करके महकमा उस जमीन को विकसित कर रहा है। और उसके खर्चे को अदा कर रहा है उसके बावजूदभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्दे ा का पाल करते हुए कम लागत परजैसे ऊचाना है वहां पर गांव में जहां सड़के बनी है और अनरू सुविधाये भी है वहां भाव ज्यादा है। मुख्यमंत्री जी के उस निर्दे ा की अलग सेपालन की है जिस गांव में इस तरह का सैक्टर विकसित होगा उसमें सिर्फ उस अधिकार नही होगा। कम कीमत की अव य इसमें ध्यान रखा गया है उस पर जा`लागत है उसमें भी कुछ न कुछ कीमत पर विभाग इस तरह से सैक्टर विकसित करके लोगों को सुविधा उपलब्ध कराएगा। यह मै माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा।

राव दान सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी बात है। कि गांव में बैटर लीविग फैस्लिटीज देने के लिए सैक्टर डिवैल्प करने की बात कही गई हैं मै आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन कस्बों में जहां की जनसंख्या ज्यादा ळै लेकिन वहां परआज कि कोई सैक्अर डिवैल्प नही किए गए है क्या ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचारधीन ह कि जिन कस्बों की जनसंख्या ज्यादा है वहां भी हुडा द्वारा सैक्टर डिवैल्प किये

जायेगे? जैसे महेन्द्रगढ़ का हैडक्वार्टर नारनौल में है लेकिन डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ़ हैा वहां पर आज तक कोई सैक्टर डिवैल्प नही हुआ।

श्री धीर पाल सिंहः स्पीकर सर, महेन्द्रगढ़ जिले का हैड क्वाट्टर नारनौल है ओर नारनौल में हुडा के सैक्टर है ओर साथ में लोगों को आवास सुविधा उपलबध कराने के लिए हाउससिंग बोर्ड भी मकान उपलब्ध करा रहा हैं जहां तक महेन्द्रगढ़ की बात है आज तक वहां के लेागों की तरफ से ऐसी कोई मांग नही की गई कि वहां परसैक्अर डिवैल्प किया जाएं उनकी मांग आने के बाद उसको एग्जामिन कर लिया जायेगा। क्योंकि हमारे पास कई ऐसे गांव है जहां प्लाट कम है और जनसंख्या ज्यादा है। मै माननीय सदस्य से कहूंगा कि अगर वहां के लेाग सैक्टर डिवैल्प करवाने के इच्छुक है तो इस बारे में आवेदन माननीय सदस्य के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और विभाग को भिजवा दें उसको एग्जामिनकरने के बार अगर वायल्य होगा तो उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री रमे ा कुमार खटकः स्पीकर सर, यह पले से ही तय है कि जिन–जिन गांवों का सैक्टर डिवैल्प करने के लिए चयन हुआ है इस बोर में निर्दे ा जारी किये गये थे कि जो पंचायत स्वेच्छिक तौर पर भूमि उपलब्ध करायेगी उसकी कीमत विभाग अदा करेगा और जहां भूमि उपलब्ध नही है वहां यह स्कीम लागू करना संभव नही हैं

श्री अध्यक्षः मंत्री जी अगर पंचायत अपनी जमीन फ्री देती है तो उसमें विभाग की उस गांव में प्लाट की कीमत में छूट देने की क्या प्लानिंग है, कृपया बताये।

श्री धीरपाल सिंहः स्पीकर सर, जमीन की लागत प्लाट की कीमत में से निकाल दी जायेगी और कई विभाग हमं जो सहयोग देते है जैसे पब्लिक हैल्थ पानी की व्यव्सस्था करता है ओर बिजली विभाग बिजली की सप्लाई करता है तो इस खर्चे की लागत ही रही जायेगी जो कि लगभग 200 रूपेय प्रति गज के हिसा से आयेगी। अगर पंचायत जमीन फ्री देती है तो एक प्लांट की कीमत लगभग 200 रूपये प्रति गज के हिसाब से आयेगी।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रका ा चौटाला): अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बनने के बाद हमने यह निर्णय लिया है पंचायत की जमीन चाहे सरकारी काम के लिए जली जाए तो वह गिफ्ट की भाक्ल में हम नही लेगें क्येांकि इस प्रकार तो पंचायत की जमीन समाप्त हो जायेगी ओर पंचायत की आमदनी समाप्त हो जायेगी। इसलिए जिस भी किसी पंचायत से कोई रकबा लिया जायेगा तो उस जमीन की कीमत पंचायत के खाते में बैंक मे जमा कर्रा जायेगी। जहां तक गांवों में सैक्टर बनाने का ताल्लुक है। दान सिंह जी ने पूछा है तभी तो हमने तजुर्बे के तौर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक–एक गांव का इस स्कीम के लिए चयन किया है फिर ब्लॉक पर भी भाुरू करेगे। हमीर मं ाा यह है कि गांवों मं जां जन्संख्या बढ गई जहां रफा हाउजत के लिए जगह नही है

और गावं सड़े रहे है। इस महकमें को जो आज तक हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण ही समझा गया है किसी ने टाउन एण्ड कण्ट्री प्लानिंग का महकमा हैफ फिर मैने कहा कि फिर गांव इसकी सुविधा से वंचित क्यों है? इसलिए हम गांवों कोयह सुविधा देने जा रहे हैं इसके हिसाब से हम यह कोि ा ा करेगे कि थोड़ी से थोड़ी कीमत पर गांवों में सैक्टर के लिए प्लाट दिये जायें क्येांकि हमें पता है कि गांवों के आदमी ज्यादा कीमत नही दे सकते। जहां तक चौधरी भागी राम जी ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों छूट देने बारे जिक्र किया तो मै उनके बताना चाहता हूं कि हुडा में इस प्रकार की छूट देने का कोई प्रावधान नही है। इसलिए इमसें सिी प्रकार की सुविधा या रियायत प्लाट में नही हो सकती है। हमारी मं ाा यह है कि गांवों के प्लोटों पर किसी प्रकार की सक्रूटिनी फीस, किसी प्रकार के कन्व ार्न चार्जिज या और किसी प्रकार के चार्जिज हम गांवों के लोगों से नही लोगे। हमारी सोच केवल मात्र एक है कि गांव की बढत्री हुई आबादी के दृश्टिगत लोगो ंको जैसे 'सरकार आपके द्वार कार्यक्रम' के माध्यम से सुविधाएं प्रदान कर रहे है उसी प्रकार से आवास की अच्छी सुविधा दे सकें। यह सरकार की सोच है।

तारांकित प्र न संख्या 1708

(यह प्र न पूछा नही गया क्योकि माननीय सदस्य श्री भीमसेन मेहता सदन में उपस्थित नही थे।)

Out Break of Dengue

1611 Sh. Dev Raj Dewan: (a) Whther the Government is aware of the fact that some deaths have been occurred in the state recentlydue to outbreak of dengue mysterious fever; and

(b) If so, the steps so far taken or proposed to be taken ot contral the said disease?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा० एम0एल0 रंगा): (क) हां जी। वर्श 2003 मे ंराज्य में डेन्गू ज्वर से 4 मृत्यु हुई (3 जिला करनाल में तथा एक जिला कुरूक्षेत्र में) इसी प्रकार जापानी बुखार से एक मौत जिला करनाल में हुई थी।

(ख) डेन्गू तथा जापानी बुखार पर नियन्त्रण पाने हेतु निम्न पग उठाए गए।

– मलेरिया, डेन्गू तथा जापानी बुखार की रोकथाम हेतु एक एक ान प्लान बनाया गया और सभी सम्बन्धित को भेजा गया।

– स्वास्थ्य कम्रचारियेां एवं बायोलोजिसटों द्वार रोग एवं मच्छज्ञें को सर्वेक्षणका कार्य नियमित तौर पर किया गया है।

– प्रभावित क्षेत्रों में डाक्टरों तथ पैरामैडीकल स्वास्थ्य कर्मचारियों की टीमों द्वारा दौरा करके रोगियों की जांच की गई

– दिन और रात में मैथालीन टेकनीकल या डैल्टामैथरीन की वाहन जड़ित म ाीन से फौगिंग करवाई गई।

– सम्भावित घरों तथा उसके आस–पास के घरों में प्लस फौग म ीन से फौगिंग करवाई गई।

– टेमीफास सं एंटी लारवल दवाई का छिड़काव किया गया।

– लोगों को स्वास्थ्य ि ाक्षा दी गई और अनुरोध किया गया किः

एडीज मच्छरों पर नियन्त्रण पाने हेतु उनके प्रजनन स्थलों जैसे कि कुलरों, टायरों, ड्रमों, होदियों, पानी की टंकियों, फूलदानों आदि को सप्ताह मे ंएक बार खाली करना।

– मच्छर भगाने वाली क्रीम का प्रयोगर करना।

– पूरी बाजू की कमीज पहनना।

– सुअरों को घरों से दूर रखना।

– रोगियों के लिए अलग वार्ड रखे गये और उन्हें मच्छरदानी उपलब्ध करवाई गई

– रोगियों का सभी आव यक उपचार किया गया।

पी0जी0आई0 चण्डीगढ़, पी0जी0आई0, रोहतक एवं एन0ए0एम0पी0 दिल्ली से इन रोगों की रोकथाम हेतु वि ाशज्ञों का सहयोग प्राप्त किया गया । वर्श 2003 में मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अन्तर्गत उपरोक्त बिमारियों पर नियंत्रण पानी हेतु

उपलबध करवाई गई रा ि ा के अतिरिक्त राज्य सरार द्वारा प्लान स्कीम में 14 लाख रूपये की रा ि ाउपलब्ध करवाई गई।

वर्श 2004 में डेन्गू तथा जापानी बुखार पर नियत्रण पानी हेतु एक एक ान प्लान तैयार कर ली गई। राज्य के सभी जिला मेलेरिया अधिकारियों एवं बायोलोजिस्टों कोएक माईक्रोप्लान बनाने हु हा गया है। ाकि इन रोगों तथा मच्छरों का सर्वेक्षण दृढ़ता से किया जा सकें।

श्री देवराज दीवानः अध्यक्ष महोदय, मै रंगा साहब के सजवां से संतुश्ट हूं सकलिए इनका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अनिज विजः अध्यक्ष महोदय, यह जो जापानी बुखार की बात गई है इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि इसका मच्छर स्वच्छ पानी मे ंपैदा हेात है और अक्सर जब चावल बायेा जाता है और उसमे ंपानी दिया जाता है उस बैल्ट के आसपास इसका ज्यादा प्रकोप होताहै। अध्यक्ष महोदय, लगभग हर वर्श इस बुखार का प्रकोप होता है, यह ठीक है कि सरकार ने फौगिंग करवा दी, अच्छी बता है लेकिन इसके प्रकोप को हर साल होने से रोका जासके और जहां–जहां पर पैडी की बैल्ट है ओर स्वच्छ पानी के साधन है वहां परयह मच्छर पैदा न हो उसके बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है?

डा० एम0 एल0 रंगाः अध्यक्ष महोदय, प्र न डेगू बुखार का चल रहा था। डेगू बुखार ओर जापीनज बुखार में थोड़ा अंतर

है। जिस प्रकारसे कोई एक दवाई लेने से एडिक्ट होता है ओर एक स्टेज ऐसी आ जातीळै जब वह दवाई उस परकोई प्रभाव नही डालती। इसी प्रकार पैडी एरिया मे जो मच्छर पैदा होतो है उस पर दवाई छिड़कते रहते है ओर बार–बार दवाई छिडकने के कारण एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब कोई दवाई उस मच्दर पर असर नही करती और मच्दर के अंदर अपना विशैलपन आ जात है ओर जब ैडी की कटाई होती है तो मजदूर लोग अपने बच्चों को पैडी के खेतों में सुलाकर ही कटाई करते है और मच्छर वही से निकलकर अपने नजदीके से नजदीक उन बच्चों परचोट करने की कोि ा ा करता है। और फिर वह विश युक्त किटाणु बच्चों के भारीर मे ंप्रवे ा कर जात है जिसे एक वि ोश प्रकार के बुखार का नाम दे दिया जाता है। एहतियात बरतने के लिए कहा गया कि धान की कटाई के वक्त बच्चां को खेत के आसपास न रखा जाये। मै सदन की जानकीर के लिए बताना चाहूंगा कि पी0जी0आई0, चण्डीगढ़ और आल इण्डिया मैडिकल इन्स्टीच्यूट, दिल्ली में भी इस पर भाोध कार्य किया गया है। हमारे विभाग ने भी भाोध किया है कि भविश्य में इस पर कौन सी दवाई छिड़की जाए जो उन पर प्रभाव कर सकसे। प्रिकॉ ानमैययर्ज जो सरकार की तरफ से किए गए है वह भी बताना चाहूंगा कि एक माईक्रो प्लानिंग स्कीम तैयार की अै। यह स्कीम अक्तूबर–नवम्बर महीने में पैडी सीजन एरिया में भाुरू की गई जिसमें स्पै ाल फोगिंग अभियान चलाया जाता है और लोगों को प्रिकॉ ान के बारे में जानकारी दी जाती है। साथ हीसाथ जितनी भी हमारी पी0एच0सीज0 है या सब सैन्टर्ज है उनमें

उचित दवाईयों उपलब्ध करवाई गई। साथ ही साथ यह भी प्रंबध किया गया कि यदि इस बुखार का कोई मरीज मिलता है तो उसको तुरन्त ही नजदीक के अस्पताल में या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुंचाया जाये ताकि सही समय पर उसका उपचार किया जा सकें। पिछले साल इस बीमारी के 598 संसपैक्टिड कैसिज आये थे जिनकों जिला अस्पताल में या किसी अन्य बड़े अस्पताल में ले गए थे जहां पर उनका इलाज करवाया गया। मै एक पूरक प्र न के उत्तर में पहले ही बता चुका हूं कि इस वक्त केसिज में से सिर्फ 4 व्यक्ति की ही मृत्यु हो पाई थी।

Investment mad in Power Sector

1711 Sh. Jasbir Mallour: Will the Chief Minister be pleased to state the investment made so far in the power sector during the regime of present Government in comparison withthe investment made, in this regard during the period from July 1991 to May, 1996 and from May, 1996 to July, 1999 together with the details thereof?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा): विवरण सदन पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

वर्तमान सरकार के भाासनकाल के दौरान 2972.34 करोड़ रूपये काएक रिकार्ड निवे ा किया गया है। जुलाई, 1991 से मई 1996 तक अवधि के दौरान 892.41 करोड़ रूप्ये तथा जून,

1996 जुलाई, 1999 तक1016.66 करोड़ रूपये का निवे ा किया गया था।

विद्युत क्षेत्र में करोडऋ रूपयेां में निवे ा का विस्तृत विवरण।

अवधि	ह.वि. प्र.नि. लि/ह. रा.बि. बो	उ.ह.वि. वि.नि. लि	द.ह.बि. वि.नि.लि	ह.वि.उ. नि.लि.	कुल रूपये करोड़ों में
जुलाई, 1991 से मई, 1996 तक	892.41				892.41
जून, 1996 से जुलाई, 1999 तक	755.88	3.03	5.33	252.42	1016.66
अगस्त, 1999 से दिसम्बर, 2003 तक	666.92	372.26	375.31	1557.85	2972.34

हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड मई, 1996 तक अस्तित्व में था इसलिए निवे ा सम्पूर्ण विद्युत क्षेत्र के लिए है।

हरियाणा राज्य बिजलीबोर्उ दिनांक 14.08.1998 से ह. वि.प्र.नि. में पुनगर्ठित किया गया था तथा 1.7.1999 से ह.वि.प्र.नि. मेंसे उ.ह.बि.वि.नि तथा द.ह.बि.वि.नि की उत्पत्ति हुई थी तद्नुसार खर्चे को प्रत्येक विद्युत निगमों में बाटा गया हैं

श्री जसबीर मल्लोरः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगाकि बिजली क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2972.34 लाख रूपये वर्तमान सरकार ने खर्च किए है। साथ ही सथ विवरा में यह भी द ार्िया गया है कि चौधरी भजन लाल जी के समय में वे चौधरी बंसी लाल जी के समय में बिजली क्षेत्र में कितना चर्ा किया गया। हमारी वर्तमान सरकारने पहली सरकारों की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा पैसा बिजली क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लगाया है। मै मुख्यमंत्री जी से जानना चाह हूं कि सरकार की तरफ से यह पैसा किस–किस क्षेत्र में बिजली को बढ़ाव देने के लए लगाया गया है। उदाहरण के तौर पर मै जानना चाहूंगा कि नए सब–स्टे ान बनाने पर कितना पैसा खर्च हुआ, नई तारें आदि बिछाने पर कितना खर्च हुआ, ट्रांसफार्मरज आदि पर कितना पैसा खर्च हुआ औरजो पुराने सब स्टे ांज थे उनकी आगुमन्टे ान आदि पर कितना खर्च हुआ।

श्री राम पाल मजारा+ अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे साथी ने खुद ही माना है कि एक रिकार्ड तोड़ प्रगति बिजली के क्षेत्र में हुई है। मै सदन की जानाकरी के लिए बता देना चाहता हूं कि वैसे तो सरकार ने हर क्षेत्र में पैसा बहुत लगाया है जिस कारण हरियाणा प्रदे ा प्रगति के पथ पर बढ़ा है। प्रदे ा को प्रगति के पथ पर लाने की धुरी बिजली है। जैसा कि मेरे सथी ने पूछा है कि विभिन्न मदों में कितना–कितना पैसा खर्च हुआ वह मै सदन की जानकारी के लिए बता देता हूं कि सबसे ज्यादा पैसा बिजली की जनरे ान के काम पर खर्च हुआ। चौधरी ताऊ देवी लाल थर्मल प्लांट के यूनिट नं0 6पर 995.03 लाख रूपये, यूनि नं0 2 पर 139.5 लाख रूपये यूनिट नं0 1 पर 15.64 लाखरूपये यूनिट नं0 11 पर 22.74 लाखरूपये यूनिट नं0 3 पर 71.08 खर्च किए गए। इसी प्रकार इसी प्लांट परयूनिट नं0 1 से 6 तक पर सामान्य कार्य के लिए 60.61 लाख रूपये खर्च किए गए। इसी प्रकार से थर्मल प्लांट फरीदाबाद पर 45.66 लाख रूपये खर्च किए गए। पि चमी यमुना हाईडल प्रोजैक्ट चरण–1 पर 10.56 लाखरूपये खर्च किए गए। इसी प्रकार से चौधरी ताऊ देवी लाल थर्मल प्लांट पानीपत के 7वें और 8वें यूनिटपरभी 862.03लाख रूपये खर्च किए गए हैं सूक्ष्मपान विद्युत परियोजना, काकरोई में 2.09 लाख रूपये खर्च किएग गए जोकि कुल मिला कर 2258.09 लाख रूपयेहुए है। इसी प्रकारसे लाईनों की बाईफरके ान करने के काम में 11 के0वी0 ए0 की लाईनों को बाईफरके ानकरने तथा प्रसार प्रणाली को सुढ्ढृ करने परसरकारने 668 करोड रूपये का निवे ा कियाा

है और 71 नये ग्रिड उपकेन्द्र बनाए गए है जिन पर 532 करोड़ रूपये का निवे ा किया है और 71 नये ग्रिड उपकेन्द्र बनाए गए है जिन पर 532 करोड़ रूपये खर्च हुए है, 240 केन्द्रोंकी क्षमता बढ़ाई गई ओर 1190 किलो मीटर की प्रसार लाईनें बिछाई गई अै अज्ञैर 29 नये 33 के0 वी0 ए0 के उपकेन्दों का निर्माण करने पर लगभग 70 करोड़ रूपये खर्च किए गये है। स्पीकर सर, इसी प्रकार से 127 उपकेन्द्रों की क्षकता वृद्धि करना इसमें भाामिल है। इसी प्रकार से भाखड़ा इकाई का नवीनीकरण करने के लिए उसका आधुनिककीकरण करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 47 करोड़ रूपये खर्च किए गए है। उत्तरी हरियाणा बिजली निगम तथा दक्षिणी हरियाणा बिजली निगम पर भी पैसा खर्च किया गया हैं स्पीकर सर, 33 के0 वी0 ए0 के एक सब स्टे ान के निर्माण पर लगभग सवा करोड़ रूप्ये खर्च हेाता है जब कि 66 के0 सी0 ए0 का सब स्टे ान बनाने पर 8 करोड़ रूपये से लेकर 20 करोड़ रूप्ये कीलागत आती है। स्पीकरसर, अगर मै सारे सब स्टे ानों के बारे में जो पैसा खर्च किया गया है वह बताऊंगा तो वह बहुत मोटी किताब है और उसको पढने में बहुत समय लग जायेगा और माननीय चौधरी भजन लाल जो फिर कहेगकि कि किताब उठाकर खड़े हो जाते है। हर भाहर, हर जिले मे ंजां पर भी यह महसूस किया गया कि पावर लोडिड लाईनें है उनको बाईफरकेट और ट्राईफरकेट किया गया है आर वहां परसब स्टे ान्ज बनाए गए हैं जिसकी वजहसे पूरी क्रिक्वैंसी की बिजली दी गई और सारे

हरियाणा के किसान, मजदूर, व्यापारी और कर्मचारी बिजली के मामले में पूरी तरह से सन्तुश्ट हैं।

सरदार नि ाान सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीस सी0पी0एस0 महोदय ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सदन में दी हैं इसमें कोई दो राय नही है कि पिछले चार वर्श के समय में बिजल के क्षेत्र में वि ोशतौर पर ध्यान दिया है और बिजली के जैनरे ान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लाईनों को ठीक किया गया है, सब स्टे ान्ज बनाए गए है लेकिन पिछले 2–3 साल से ग्राउण्ड वाटर नीचे जाने की वजह से वे टयूबवैल्ज जो पहले कमपावन की मोटरों से चलते थे यानि 5 हॉस पावन, 10 हॉस पावर या 15 हॉस पावर की मोटरों से चल रहे थे अब उनकी जगह पर 25 से 30 हॉस पावर की मोटरे लगाते है जिसके कारण सारेसब स्टे ान ओवर लोडिड हो गए है वि ोशकर पैडी ऐरियाज के सब स्टे ान ज्यादा ओवर लोडिड हो गए है। मै आपके माध्यम से सी0 पी0 एस0 महोदय से यज यह जानना चाहूंगा जो सब स्टे ान ओवर लोडिड हो गए है क्या पैडी सीजन से पहले महकमा उन ट्रांसफारमर्ज को बदलने के बारे कोई विचार कर रहा है?

श्री राम पाल माजराः स्पीकर सर, सब स्टे ान बनाने के लिए भौडयूल टाईम होता है 33 के0 वी0 एस0 का एक सब स्टे ान बनाने में लगभग एक वर्श का समय लगता है। जितनी भी एनाउसंमैट्स होती है या हुई है उनकी लिस्ट यहां पर विधान सभा में प्रस्तुत की गई है कि कहां कहा पर 33 के0 वी0 ए0 ओर

66 के0वी0 ए0 सब स्टे ान पूरे किए जा रहे है। औरकमी ांड भी हो रहे है। जैसा कि मेरे माननीय साथी ने पैडी ऐरिया के बारे में कहा है तो मै इनको कहना चाहूंगा कि अगर इनके ध्यान में कोई ऐसा सब स्टे ान है तो यह बात दे उसका रिव्यू करके और एग्जामिन करके जल्दी ही पूरा करवाने का कार करेगे।

श्री जयबीर मल्लौरः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय सी.पी.एस. महोदय से रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि चौड़मस्तपुर 132 के0पी0ए0 का सब स्टे ान मेरे हल्के में पड़ता है। ओर लिस्ट में उसकानाम भी है, जिन सब स्टे ान की क्षमता में वृद्धि करने की बात कही है लेकिन इस सब–स्टे ान की क्षकता में वृद्धि करने की बात कहीहै लेकिन इस सब स्टे ान पर आज तक कोई काम नही किया गया हैं 220 के0पी0ए0 सब स्टे ान तेपला का उद्घाटन माननीय मुख्य मंत्री जी करके अये थे उस अधिकारियों ने यह बात कही थी कि जिस वक्त यह चालू हो जाएगा। उसके बार हम चौड़मस्तपुर सब स्टे ान की क्षमता बढ़ाने का काम भ्रु कर देगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदनहै कि इस सब स्टे ान का काम जल्दी भ्रु किया जाए। इसके साथ ही मै यह निवेदन करना चाहूंगा कि दुराना गांव में 66 के0पी0ए0 का सब स्टेश्ज्ञन बनाने के लिए पंचायत ने जमीन दे दी है ओर अधिकारीगण मौके पर जा कर सर्वे भी कर आये है। अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सी0पी0एस0 महोदय इन सब स्टे ानों का काम जल्दी भ्रु करवाने के लिए आ वासन देने की कृपा करेगे?

श्री कृश्ण लाल पंवारः अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी के राज में ताऊ देवी लाल थर्मल प्लांट का दूसरा यूनिट जनवरी, 1999 में 110 मैगावाट से बढ़ाकर 11 मैगावाट का करने का काम ए0बी0बी0 कम्पनी को 300 करोड़ रूपये के ठेके पर दिया गया था और वहा काम चार साल मे ंपूरा किया जानाथा लेकिन उस प्लांट का कमा चार साल तक बंद रहा और इसकी वजह से ए0बी0बी0 कम्पनी ने सरकार को करोड़ो रूपये का चुना लगाया है वर्तमान सरकार ने वही यूनिट चालू वित्त वर्श में 39 करोड़ मे ंचालू कर दिया है। जिससे पब्लिक के 261 करोड़ रूप्ये बचाए है। इस बारे में मैने पहले भी प्र न किया था और मुझे यह जवाब दिया गया था कि इस बारे में इन्कवायरी करवाई जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस विशय में कोई इन्क्वायरी करवाई गई है, अगर करवाई गई तो उसकी रिपोर्ट आई है?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रका ा चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मै इस विशय मे यह बताना चाहूंगा कि यह केस आर्बीट्रे ान मे ंचल रहा है। इसलिए इस विशय में ज्यादा चर्चा की जा सकती है। उसका जो भी फैसला आएगा, उसी के मुताबिक कार्यवाही की जाएगी।

श्रीमती अनिता यादवः अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के साल्हावास में रैडिडै ि ायल ऐरिये के ऊपर से बिजली की लाईनें गुजरती है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को हर वक्त मौत का

भय बना रहता है। क्या मंत्री जी वहां से उन लाईनों को हटाने का कश्ट करेगे?

श्री ओम प्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, अमूमन कई जगहां से ऐसी ि ाकायतें मिलती है कि बिजली की लाईनों पहे खीची गई थी और मकान बाद में बनाए गए थे। लेकिन हमें ऐसी कोई ि ाकायत नही मिली हैथ्क पहले मकान बनाए हुए है ओर उनके ऊपर से बिजली की लाईन खीची गई हो। अब जिन्होने मकान बनाए है उनको देखना चाहिए कि वे अपने मकान वहां पर न बनाए। हमारे पाल लाल डोरे की ऐसकी कोई ि ाकायत नही आइ है। अगर काई ऐसी ि ाकायत आएगी तो वहां से उन बिजली की तरों को हटवाने का काम किया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि लाईनें बिछाने के बाद लेाग मकान बना देते है जोकि उनको देखना चाहिए कि वे बिजली की लाईन के नीचे मकान न बनाएं। अध्यक्ष महोदय, जो जरूरी काम है उनको हमारी सरकार करेगी। ऐसा नही है कि मकानों को तोड़ कर नहरें बनवा दी है ओर मकानों के ऊपर से बिजली की लाईनें बिछा दी गई है। हमारी सकरार का यह फैसला है कि गांवों में मकानों, स्कूलों ओर चाहे जोहड़ों के ऊपर से बिजली की लाईनें जाती है उनको हटाने का काम किया जाएगा। चाहे उनको कलम्प लगा कर या खम्बे लगाकर हटाने का काम किया जाएगा। चाहे उनको कलम्प लगा कर या खम्बे लगाकर हटाया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों की जान माल की रक्षा करेगें।

Enactment of Law to check Damage of Raods

1698 Sh. Rajinder Singh Bisla: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to enact any law to chiec the damage of the roads in in the State on the Pattern of the Control of National Highway (Land the Traffic) Act, 2002 enacted by the Government of India; if so, the details thereof?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा): नही श्रीमान जी।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला: अध्यक्ष महोदय, मैने इस प्र न के माध्यम से इस सन का, सरकार का ओर खासकर के मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्शित करने का प्रयास किया है। इस प्र न से मैने यह जानकारी दलेने काप्रयास किया है कि भारत सरकार ने पालियामैंट में एक्ट बनाया हुआ है। The Control of National Highways (Land & Traffic), Act, 2002 जिसके अनुसार नै ानल हाई–वेज सैन्टर गवर्नमैंट की प्रापर्टी समझी जाती है। इसमें सड़कों की डैमेज का, एन्क्रोचमैंट करने का फंला–फंला अधिकारी को अधिकारी दिया गया है और फलां–फलां अधिकारी का कर्तव्य भी है, एम्पावर्ड है कि जो भी इस अधिनियम का उल्लंघना करता है। वह उसके खिलाफ एक ान ले। आज सार हिन्दुस्तान में सबसे अच्छा सड़कों का नेटवेर्क हमारे प्रदे ा के अंदर ही है। लोकिन कही भी किऐ एक्ट, रूल या नोटिफिके ान में किसी भी अधिकारी को यह पावर नही दी गयी है ओर न ही

इस बारे में किसी की कोई अकांउटेबिलिटी हैं अगर एक आदमी लापरवाही से पानी डालकर सड़का को डैमेज करता है तो इससे बड़ा भारी नुक्सान होता है ओर सरकार का इस परकाफी पैसा खर्च हेाता है लकिन सड़क को डैम्ेज करने वाले के खिलाफ कोई एक ाननही लिया जाता है। ओर प्रायः अधिकारी वर्ग द्वारा यह कह दिया जाता है इस बारे मे किसी को पावरनही है, कोई एक्ट नहीहै, कानून नही है मै आपके माध्ये से श्री रामपाल माजररा जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि अपने उत्तर में केवल 'नो सर' करने के बजाए जब ीाी इनको टाईम मिले तो ये अधिकारी वर्ग को यह आदे ा दें कि यह जोएक्ट है इसमें वे गो थ्रू हो। मेरा इनसे यह निवेदन है कि विधान सभा का तो काम ही कानून बनाना है और पुरान कानूनों में अमैंडमैंन्ट करना है। सबसे जरूरी काम को यही है कि विधान सभा लैजिसले ान बनाये। इसलिए मै दोबारा से उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि खाली 'नो सर' कहने के बजाए कम सक कम इस बारे में आप गौर करें ओर अगर आप कन्सिंस हो जाते है, समझ जाते है है तो इस बोर में एक नोटिफिके ान जारी होनीचाहिए या इसबारे में एक कानून बना दिया जानाचाहिए ताकि करोड़ें रूपये की जो रोडज डैमेज हो जाती है वह डैमेज न हो। इसलिए मै माजरा जी से निवेदन करते हुए इस बारे में आ वासन चाहूंगा।

श्री रामपाल माजराः स्पीसर, इस सम्बन्ध में वैसे तो Control of National Highway (Land and Traffic) Act, 2002 है

और जो Punjab Scheduled Roads and Controalled Areas Restricition of Unregulated Development Act, 1963 है उसमें ज्यादातर प्वायंटस आलरेडी कवर किये गये है फिर भी बिसला जी ने एक बहुत ही अच्छा मामला उठाया है। इन्होने कहा है कि जो राश्ट्रीय मार्ग नियंत्रण (भूमि तथा यातायात) अधिनियम, 2002 है इसको हरियाणा प्रदे ा में भी इनकोरपोरेट करें। इनकी बात सही है लेकिन स्पीकरसर, इसके अंदर कई प्वायंट्स हैं मै थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा। उच्च मार्ग के भिन्न–भिन्न प्रकार के यातयात का नियमंत्रण, उच्च मार्ग पर अस्थाई तौर पर यातायात को बंद करने के बारे में, उच्च मार्ग को स्थाई तौर पर बंद करना या रोकने के बारे में कार्यवाही करने य उच्च मार्ग पर एक वि ोश श्रेणियों के यातायात के प्रयोग करने पर पाबंदी, उच्च मार्ग के क्षतिग्रस्त एवं रोकथाम ओर वहानों एकव प ाुओं को खतरनांक हालत में छोड़ने के लिए उन्होने अधिनियम बनाया है। चूंकि बिसला जी एक बुद्धिजीवी ओर अच्दे लायक विधायक है इन्होने एक अच्छा मामला उठाया है। इसलिए हम इसको स्टडी करकेगे ओर साथ ही हम यहां के हालात को भी स्टडी करके अगर यह ऐप्लीकेबल होगा तेा हम इस बारे में कानून बनाएंगे। इन विपक्ष के भाईयों ने तो कोई सुझाव दिया नही लेकिन बिसला जी हमारी साथी है इन्होने अच्छा सुझाव दिया है अच्दी बात है इसको हम इनकोरपोरेट करेगे।

श्री पूर्ण सिंह डाबड़ाः स्पीकर साहब,ा सुप्रीम कोट्र का एक आदे ा सपीड बेकर्ज के बारे में आया हुआ है। आजकल सड़कों के ऊपर जो हाई स्पीड की गाड़िया चलती है उनकी ग्राउंड क्लीयरैन्स बहुत थोड़ी होती है खासतौर से इस तरह की गाड़िया जब से हमारे मुल्क में आयी है तब से स्पीड ब्रेकर्ज को लेकर बहुत दिक्त आ रही है लेकिन इस बारे में कही पर भी किसी का ध्यान नही जा रहा है। हाइवेज पर सोर ब्रेकर्ज लीगली अनअथोराइज्ड है अब तोएक इजी वे आउट देखा हुआ है। हकि अगर कही किसी रोड़ पर किसी की डैथ हो जताी ळै तो स्पीड ब्रेकर्ज बना दिए जाते है और फिर मन मर्जी से उनको हाई लेवल का बना दिया जात है। तो This is a problem Sir, इसके कारण काफी कॉस्टली कॉस्टली व्हीकल्ज टूट`के है ओर जब इन स्पीड ब्रेकर्ज पर ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी दोबारा से उठो है तो तेल के खर्चे में भी दो तीन किलोमीटर का डिफरैन्स आ जात है। ऐक्सीडैंट के चांसिज और दूसरी चीजें आ जती है स्पीड ब्रेकरका इसमें मार्क नही है। इस विशय में मै चाहूंगा कि महकमा इस पर रो ानी डाले?

श्री रामपाल माजराः अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय काबिल साथी ने एक बहुत ही अच्छा प्र न रेज किया है मै बताना चाहूंगा कि नै ानल हाइवे पर तो स्पीड ब्रेकर नही। स्टेट हाईवे पर कही पर एक दो जगह होते है। जहां तक इस बारे में सैन्ट्रल गवर्नमैंट की गाईडलाईन्ज है, वर्ल्ड बैक की गाईडलाईन्स है वह

यह है कि स्पीड ब्रेकर नही होने चाहिए। लेकिन स्पीकर सर, हरियाणा प्रदे ा में हमने इस प्रकार की सड़कें बनाई है, रण थ्रू सड़के बनाई है इतनी बढ़िया सड़कें बनाई है कि हरियाणा प्रदे ा के लोग मांग करने लग एग है कि स्पीड ब्रेकर भी जरूर बनाये जाए। और स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग को लेकर कई जगह लोगोंने जाम लगाए है। हमने इतनी मोटरेबल सड़के बनादी कि 130–140 कि0मी0 प्रति घण्टा की रफ्तार से गाड़िया चलती है। फिर भी नॉमर्स के मुताबिक हम इसकों ऐग्जामिन कर लेगै। हम तो स्पीड ब्रेकर नही बनाना चाहते है लेकिन लोगों की मांग पर बनाने पड़ते है। क्योंकि हम लोग डैमोक्रेटिक है, हमीर पार्टी डैमोक्रटिक है ओर हमारे मुख्यमंत्री जी भी डैमाक्रेटिव है। सड़कों पर स्पीड से दौड़ती हुई कारों को देखकर गांव के लोग भयभीत हो जाते है ओर मांग करते है कि इस गांव में जरूर स्पीड ब्रकर बनाना चाहिए। 'सरकार आपक द्वार' कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्रल जी के समक्ष लोगों ने यह मांग रखी है कि यहां–यहां पर स्पीड़ ब्रेकर बनने चाहिए। हम अगर स्पीड ब्रेकर न भी बनाएं तो कई जगह लोग खुद बना लेते है। मै अपने साथी को आ वस्त करना चाहूंगा कि हम कोि ा ा करेगे कि स्पीड ब्रेकर न बनाए जाएं ओरलोगों की मांग पर बने भी तो स्लोप में बनने चाहिए। (विध्न)

आई०जी० (रिर्टायड) भोर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सड़के बनती है लेकिन उनमें क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज किया जात है

इसके लिए कोई न कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चहिए। नही तो होता क्या है कि आगे सड़क बनती जाती है और पीछे टूटती जाती है। इस प्रकार सड़के बहुत जल्दी टूट जाती है।

श्री अध्यक्षः इस सप्लीमैंट्री का इस सवाल से कोई संबंध नही है। इसलिए आप बैठ जाएं।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रका ा चोटाला): अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो चीज बनती है वह टूटती भी है, आदमी पैदा होताहै वह मरता भी है यह प्रकृति का नियम है और इस नियम में कोई रूकावट नही की जा सकती है। लेकिन कही कोई गलत मैटीरियल लगा हो, कोई बेकायदगी हुई हेा तो बताए। क्वालिटी कंट्रोल का अलग से महकमा बना हुआ है यदि कोई पर्टिकुलर ि ाकायत हो तो आप हमें हम उसको विभाग से ऐग्जामिन कराएंगे। मैने कल भी चर्चा के दौरान बताया था कि बारि ा की वजह से सड़के टूटी है और टूटती है क्योंकि पानी और लुक का बैर है। फिर भी हम सारी की सारी सड़कों की रिपेयर कराएंगे। हम हर संभव प्रयास करते है। कि अच्दी क्वालिटी की सड़कं बनें। हपूरा दे ा इस बात की सराहना कररहा है कि हरियाणा प्रदे ा की सड़कें बहुत अच्दी है यदि कही कोई दिक्कत है ओर आपके नोटिस में है तो आप पटिकुलरली बताएं कि कौन सी सड़क खराब है। या फलां ठेकेदार ने बेकायदगी की है तो मै ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस आ वासन देता हूं कि हम उनके खिलाफ ऐक ान लेगे।

Teaching of Yoga in Schools

1622 Sh. Kanwar Pal: Will the Minister of state of State for Ducation be pleased to state whther there is any proposal under consideration of the Governemnt make the education of Yoga as a compulsory subject in the schools; if so, the time by which it is likely to be made compulsory?

ि ाक्षा राज्य मंत्री (चौधरी बहादुर सिह): जी नही,

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब प्र न काल समाप्त होता है।

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नो के लिखित उत्तर

1633 Sh. Karan Singh Dalal: Will the Minister for Transport be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide free travelling facilities in Haryana Roadways Buses to allthe Categories of handicapeed persons in The state along witht he Criteria to be adopted?

परिवहन मंत्री (श्री अ ाोक कुमार): श्रीमान जी, 100 प्रति ात भाारीरिक विकलांग एवं अन्धे व्यक्तियों को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में मुक्त यात्रा का सुविधा पहले ही प्रदान की हुई है। इस सम्बन्ध में ऐसा कोई और प्रस्ताव सरकार के विचारधीन नही है।

Makaing of water Course Pucka inDabwali Constituecny

1597 Sh. Sita Ram: Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) Whether there is any proposal under considerationof theGovernment to make water courses "pucka'' in Dabwali Constituency; and

(b) If so, the time by which the above said water courses are likely to be made ''pucka''?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रका ा चौटाला): (क) हां, श्रीमान जी, भाखड़ा कैनाल कमाण्ड में खालों को पक्का करने के लिए योजना का भुभारम्भ नहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 01.01.03 हो चुकाह ै। इस योजना के द्वारा 31946 लाख रूपये की लागत से 239154 हैक्टर एरिया को लाभ पहुंचेगा। यह योजना हरियाणा के आठ जिलों अम्बाला, करनाल, कुरूक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार फतेहाबार और सिरसा में क्रियान्वित होगी। डबवालल विधानसभा क्षेत्र में इस योजना के अन्तर्गत खालों को पक्का किया जायेगा।

(ख) डाबवाली विधान सभा क्षेत्र जिला में 14 ने खालों पर काम भुरू हो चुका है तथा वह काम धनरा ि ा उपलबध होने पर पूरा किया जायेगा।

Opening of P.H.C. in Roopbadaka and Uttawar

1589 Sh. Bhagwan Sahai Rawt: Will the Minister of State for Health be pleased to stae:-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to open a new P.H.C. in Roopbadaka and Uttawar in Hathin Constituency; and

(b) If so, the time bywhich tht aforesaid proposal is likely to be implemented?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डां० एम0एल0 रंगा): (क) रूपबड़का में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रस्ताव नही है। रूपबड़ाका के नजदीक, उत्तावड़ में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहले से कार्यरत है।

(ख) लागू नही होता।

Repair of Roads in Yamuna Nagar Constituency

1608 Sh. Malik Chand Gambhir: Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the following damaged roads in Yamuna Nagar Constituency are likely to be repaired-

1. Yamuna Nagar to Shadipur;

2. Shadipur roads to Raipur Kami Majra;

3. Road of Model Town, Yamuna Nagar;

4. Roads of Model Town Colony, Yamuna Nagar; and

5. Hamida Colony to Panjupur Parallel to Canal?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रका ा चौटाला): श्रीमान जी, माडल टाऊन यमुनानगर में प्र न की क्रम संख्या तीन व चार की सड़कों की मरम्मत पहले ही की जा चुकी है।

भाादीपुर–रायपुर कामी माजरा सड़क तथा हमिदा कालोनी से पंजूपुर तक सड़क जो नहर के समान्तर है, की मरम्मत अगल तीन महीनों में किए जाने की सम्भावना है। यमुनानगर– ाादीपुर सड़क की मरम्मत का कार्य प्रदान मंत्री ग्रांम सड़क योजना के अनतर्गत परियोजना की स्वीकृति के उपरान्त किया जायेगा। इस दौरान इस सड़क की मरम्त पैच लगा करकी जा रही है।

Repair of Road in Village Swarupgarh

1647 Sh. Jagjit Singh: Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that road passing thourgh village Swarupgarh, Tehsil Charkhi Dadri, District Bhiwni which leads to Delhi (Via Imlota) is in a very bad condition; if so, whether is any proposal under consideration of the Government to repair the said road?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रका ा चौटाला): हां, श्रीमान जी। उक्त सड़क की मरम्त का प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है।

Number of Haryana Roadways Buses

1658 Sh. Puran Singh Dabra: Will the Minister for transport be pleased to state:-

(a) The total number ofbuses in Haryana Roadways as on 24-07-99; and

(b) The total number of buses, at present, in the Haryana Raodways together with the number of new buses introduced from the period from 25-07-1999?

परिवहन मंत्री (श्री अ ोक कुमार): श्री मान जी,

(क) हरियाणा राज्य परिवहन में 24.07.99 को कुल 3728 बसें थी।

(ख) हरियाणा राज्य परिवहन में 31.02.2003 को कुल 3451 बसें थी दिनांक 25.07.99 से 31.01.2004 तक हरियाणा राज्य परिवहन की 2144 पुरानी बसों को नई बसों से बदला गया है।

Construction of the Buidling for New Jails

1653 Sh. Suraj Mal: Will the Chief Minister be pleased to state the numher of building of new jails constructed in the state during the periof from the year 2002 to date?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रका ा चौटाला): हरियाणा राज्य में तनी नई जेलों कइ इमारतों का निर्माण कार्य वर्श 2002 से अब तक निर्माणधीन है, जिनके नाम निम्नलिखित है:—

1. जिला जेल, गुडगांव (प्रथम चरण, जिसकी क्षमता 1328 बन्दियों को रखने की है, का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसका प्रयोग 1611.2003 से किया जा रहा है।)

2. जिला जेल, करनाल।

3. जिला जेल, नारनौल।

Protecting Animals from disease

1759 Sh. Nafe Singh Jundla: Will the Minister of State for animal Husbandry be pleased to state whether ther is any scheme under consideration of the Government to stop the spread disease in animals and to protect their health from the communicable diseases in the state. if so, the details?

Repair of Roads

1655 Sh. Krishan Lal: Will the Chief Minster be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the following damaged roads of District Karnal-

(i) Aincla to Padha via Balpabana;

(ii) Kurlan to Salwan;

(iii) Kurlan to Jalmana;

(iv) Assandh to Deragama;

(v) Assandh to Chugama;

(vi) Assandh to Deragujrabian;

(vii) Kond road to Kutana;

(viii) Mormajra to Salwan;

(ix) Salwant to Kubulpurkhera; and

(x) Salwan to Tejupurkera; and

if so, the time by which the siad roads are likely to be repaired?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रका ा चौटाला): हां, श्रीमान जी। इस स्थिति में कोई नि ित समय बताना सम्भव नही है।

Upgradation of Primary/Middel Schools

1675 Smt. Anita Yadav: Will the Minister of state for education be pleased to state-

(a) Whether ther eis any proposal under consideatio of the Government to upgrade the Government, Primary Schools/Middle Schools of Koharar, Kheri, Jakhala and Bithia of Salhawas constituecny to Government Middel Schools/High Schools; and

(b) If so, the time by which the aforesaid schools are likelyto be upgraded.

ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्री बहादुर सिंह) नही श्रीमान जी,

अताराकिंत प्र न एवम् उत्तर

Old Age Pension

183 Sh. Karan Singh Dalal: Will the Minister of state for Social Welfare be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to raise the amount of olf age pension in the State in near future?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री रिसाल सिंह): नही श्रीमान।

Recruitment of Police Constables

184 Sh. Karan Singh Dalal: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) The district wise number of constables, if any, recruited in the State during the year 2002-2003; and

(b) The criteria of selection of said constables in the State?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रका ा चौटाला): हां श्रीमान जी, मांगा गया उत्तर विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

वर्श 2002–2003 में जिलावार की गई भर्ती का विस्तृत विवरण

क्रम सं०	जिला का नाम	भर्ती किये गये सिपाही

1	हिसार	317
2	भिवानी	554
3	सिरसा	289
4	फतेहाबाद	133
5	जींद	468
6	रोहतक	267
7	सोनीपत	290
8	पानीपत	161
9	करनाल	202
10	झज्जर	259
11	अम्बाला	165
12	यमुनानगर	122
13	कैथल	247
14	कुरूक्षेत्र	190
15	पचंकुला	48

16	गुडगांव	166
17	फरीदाबाद	152
18	नारनौद	212
19	रिवाड़ी	142
20	चण्डीगढ़	11
21	पंजाब	13
22	राजस्थान	9
23	उत्तर प्रदे ा	10
24	दिल्ली	8
	कुल	4435

सिपारियों के चयन करने का तरीका

पुलिस सिपाहियों की भर्ती के लिए सं ाोधित पंजाब नियमों, हरियाणा राज्यार्थ के अनुसार की जाती है। सिपाही की भर्ती के लिए उम्मीदवार का कद कम से कम 5'–9'' (पांच फुट नौ इन्च तथा सामान्य छाती पैमाईश 1–5 इन्च (एक इन्च एवं आधा इन्च) विस्तार सहित 33 इन्च हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एव पिछड़े वर्ग के प्रवर्गो से सम्बन्धित उम्मीदवारों के लिए भाारीरिक माप में ऊंचाई व छाती की पैमाई ा के मा में एक इन्च

की सीमा तक छूट दी जाती है। उम्मीदवार की आयु 18 वर्श से कम ओर 27 वर्श से अधिक नही होनी चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गो के प्रवर्गो से सम्बन्धित उम्मीदवों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्श तक की छूट दी जाती हैं सिपाही के रूप में चयन लिए पात्रता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम भौक्षणिक अर्हत्ता मान्यता प्राप्त बोर्ड/यूनिवर्सिटभ से 10+2 पास है परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा किसी भी जाति का भूतपूर्व सैनिकों की अर्हत्ता दसवी पास है। भाारीरिक माप के आधार पर योग्य पाए गए उम्मीदवाों की भाारीरिक दक्षता परीक्षा ली जातीह ैं जिसके कुल अंक 20 है। जो उम्मीदवार कम से कम 9 अंक भाारीरिक दक्षता परीक्षा मे प्राप्त करता है उनका साक्षात्कार/पुलिस सेवा के लिए योग्यता की जानकारी के लिए लिया जात हैं साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षा के केवल 15 अंक होते है। भाारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता सूचि बनाई जाती है। सामान्य प्रवर्ग के पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं भूतपूर्व सैनिकों प्रवर्ग के उम्मीदवारों की पृथक–पृथक योग्यता सूचि तैयार की जाती है।

Vacant Posts of Judicial Officers

185 Sh. Karan Singh Dalal: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) Whether any posts of Judicial Services are lying vacant in the State at present; and

(b) If so, whether there is any proposal under consideration of the Government to fill up the said vacancies together withthe criteria therofo?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रका ा चौटाला): (क) इस समय हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक भााखा) के संवर्ग में 75 तथा वरिश्ठ न्यायिक सेव में 16 रिक्त्यां है।

(ख) हरियाणा लेाक सेवा आयोग ने हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक भााखा) की 75रिक्तियों को भरने हेतु अपनीसिफारि ो भेजने के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन कर लिया है।

हरियाणा राज्य में अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायधी ा (वरिश्ठ न्यायिक भााखा) के 16 पदों को हरियाणा के वकीलों के समुदाय से सीधे भर्ती द्वारा भरन`हुतु उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.12.2003 को अधिसूचना जारी कर दी गई है और मामला उच्च न्यायालय के विचारधीन है।

हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक भााखा) के उम्मीदवारों के चयन हेतू तरीका निम्न प्रकार है:–

(1) किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तक तक अर्हक नही विचारा जायेगा जब तक वह मौखिक सहित सभी पेपरों में कुल मिला कर कम से कम 50 प्रति ात अंक प्राप्त नही कर लेता।

(2) अर्हक उम्मीदवारों का योग्यता क्रम हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित पेपर तथा मौखिक परीक्षा में प्राप्त किए गए कुल अंकों के अनुसार कड़ाई से नि ि चत किया जाएगाः

परन्तु दो या उससे अधिक उम्मदवों द्वारा बराबर अंक प्रापत करने की द ाा में आयु में बड़े उम्मीदवार को योग्यता क्रम में ऊपर रखा जाएगा।

(3) अधीन सिविल न्यायधी ा (कनिश्ठ मण्डल) के रूप में नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा चयनित उम्मीदवारों के नाम विज्ञापित रिक्तियों से अधिक 30 प्रति ात की सीमा तक चयन के क्रम में उच्च न्यायालय रजिस्टर में प्रविश्ठ किए जाएंगे, ताकि किसी कारण से न भरे गए भोश विज्ञापित पदों के लिए किसी अनुशगिकता को पूरा किया जा सकें।

निलम्बित सदस्य श्री रघुवीर सिह कादियान तथा श्री जयप्रका ा बरवाला को वापस बुलाने के लिए अनुरोध करना।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः स्पीकर सर, हमारे दो माननीय सदस्य विधान सभा के सत्र से बाकी समय के लिए निलम्बित कर दिये है। मेरा सरकार से निवेदन है क उनको दोबारा से सदन में वापस बुला लिया जाये क्येां यह इस सरकार की टर्म का आखिरी सै ान है।

श्री अध्यक्षः अब बजट पे ा होगा। आज कोई जीरो ओवर नही होता इसलिए आप बैठ जाइए।

ध्यानकर्शण प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर सर, मैन एक कालिंग मो ान regarding increase of charges for medical treatment in the State of Haryana दिया था उसका फेट क्या है?

श्री अध्यक्षः आपका कालिंग अटैं ान मो ाहास्पिटल्ज के बारे में था वह कल के लिए ऐडिमिट कर लिया है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर सर, मैने एक और ऐडजर्नमैंट मो ान ऐप्लीके ान ऑफ वैल्यू एडिड टैकस सिस्टम के बारे में दिया था उसका फेट क्या है?

श्री अध्यक्षः आपका वैट के बारे में जो ऐडजर्नमैंट मो ान था वह डिअलाउ कर दिया है।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रका ा चौटाला): अध्यक्ष महोदय, ये सम्मानित सदस्य कई मर्तबा इस महान सदन के सदस्य रह चुके है और मंत्री जी रहे है, इनको मालूम हेाना चाहिए कि जिस दिन बजट पे ा होता है उस दिन जीरों आवर नही हेाता परन्तु ये मानते ही नही है। भजन लाल जी इनको आप समझाओं। इनको इतनी समझ नही है। भजन लाल जी और भूपेन्द्र हुड्डा दोनों बैठे हुए है फिर भी कैप्टन खड़े हो जाते है। क्या करें इनका। (विध्न)

वर्श 2004–2005 के बजट अनुमान प्रस्तुत करना

Mr. Speaeker: Now, Finance Minister will present the Budget Estimates for the year 2004-2005

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, मै इस गरिमामय सदन में 2004—2005 का वार्शिक बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं।

2. माननीय सदस्यों को विदित है कि हमारे दे ा ने गत वर्शों में भाुरू किये गये प्रमुख आर्थिक एवं ढांचागत सुधारों की बदौलत आर्थिक भाक्ति की नई ऊंचाईयों को छुआ है। हरियाणा के लाभों को समेकित करके अपने आर्थिक आधार को सुदृढ़ करने में अग्रणी राज्य रहा है। यह इस सरकार का पांचवा बजट है। हमने पिछले वर्शों की भांति आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के निर्माण पर वि ोश बल के साथ गति ील आर्थिक विकास पर ध्यान दिया है। हम अपने मुख्यमंत्री के कु ाल नेतृत्व में लोगों के सक्रिय में लोगों के सक्रिय सहयोग से प्रदे ा की आर्थिक स्थिति को दुरूस्त रखने में सफल रहे है।

राज्य की अर्थ व्यवस्था

3. राज्य की आर्थिक नीति में अर्थ—व्यवस्था से सभी क्षेत्रों के समेकित विकास की परिकल्पना की गई है। हरियाणा के आर्थिक सर्वेक्षण, जो माननीय सदस्यों को पहले ही उपलब्ध करवाया जा चुका है, में राज्य की समग्र आर्थिक स्थिति पर प्रका ा डाला गया हैं हरियाणाके सकल राज्य घरेलू उत्पाद में

स्थिर मूल्यों (1993–94) पर 5.2 प्रति ात की वृद्धि हुई हौर यह वर्श 2001–02 में 35062 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्श 2002–03 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र के अं ादान में 0.8 प्रति ात की मामूली कमी अई, जबकि द्वितीय और तृतीयक क्षेत्रों के अं ादान में क्रम ाः 5.8 प्रति ात और 9.2 प्रति ात की वृद्धि हुई। परन्तु राज्य की अर्थव्यवस्था की ढांचागत संरचना से पता चलता है कि प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृशि क्षेत्र भाामिल है, अभी भी प्रमुख क्षेत्र है, बावजूद इसके कि राजय की अर्थ–व्यवस्था में इसका योगदान वर्श 1993–94 में 42.5 प्रति ात से कम होकर वर्श 2002–03 में 29.4 प्रति ात रह गया है। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के अं ादान वर्श 2002–03 में बढ़कर क्रम ाः 28.0 प्रति ात और 42.6 प्रति ात हो गया, जबकि वर्श 1993–94 में यह क्रम ाः26.2 प्रति ात और 31.3 प्रति ात था। इसके स्पश्ट होता है कि राज्य की अर्थ व्यवस्था सही दि ाा में आगे बढ़ रही है।

5. स्थिर मूल्यों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय वर्श 2002–03 में बढ़कर 14757 रूप्ये हो गई, जबकि वर्श 2001–02 में ह 14250 रूपये थी। वर्तमान मूल्यों के अनुसार प्रति व्यक्ति आयक वर्श 2001–02 में 24820 रूपये से बढऋकर वर्श 2002–03 में 26632 रूपये हो गई है।

6. वर्श 2003–04 के दौरान मूल्य वृद्धि जारी रही है। अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य संचकांक (आधार 1982

= 100) नवम्बर, 2002 में 489 से बढ़करनवम्बर, 2003 में 504 हो गया। मूल्य सूचकांक में यह वृद्धि 3.1 प्रति ात है। इसी प्रकार, हरियाणा राज्य श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1982 = 100) नवम्बर, 2002 से नवम्बर, 2003 की अवधि में 435 से बढ़कर 445 हो गया। यह वृद्धि 2.3 प्रति ात हैं

7. माननीय सदस्यों को यद ोगा कि मैने अपने पिछले बजट भाशण में नौंवी पंचवर्शीय योजनावधि के दौरान प्राप्त उपब्यिों की स्थिति और दसवी पंचवर्शीय योजना बनाने के लिए अपनाई गई नीति का विवरण दिया था। संक्षिप्त में, राज्य की दसवी पंचवर्शीय योजना के लिए 12000 करोड़ रूपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है, जिसमें सामाजिक सेवाओं के विस्तार और आर्थिक आधारभूत संरचना में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

(इस समय माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पदासीन हुए)

वार्शिक योजना 2003–04

8. राज्य सरकार ने वार्शिक योजना 2003–04 के लिए 2100 करोड़ रूपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया। परन्तु, योजना आयोग ने संसाधनों कीसमीक्षा करने के उपरान्त राज्य योजना कापरिव्यय 2091 करोड़ रूपये निर्धारित किया। उपाध्यक्ष महोदय,वर्श 2003–04 के दौरान राज्य के संसाधनों पर अत्यधिक दवाब रहा। वर्श के दौरान बजट क बाद अनेक ऐसी गतिविधियां

हुई, जिनका योजनागत संसाधनों की उपलभ्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। केन्द्रीय करों के हमारे हिस्से में 38.49 करोड़ रूपये की कमी आई ओर यह 640.65 करोड़ रूपये से कम होकर602.16 करोड़ रूपये की कमी आई। हमें आव यक जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 350 करोड़ रूपये का योजनेतर खर्च स्वीकृत करना पडा स्थानीय क्षेत्र किवास कर से प्राप्त आय ग्रामीण तथा भाहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करने के ि लए 41.70 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ा। बिजली निगमों की देयता के एकबारगी निपटान की वजह से हमें 174 करोड़ रूपये की अतिरिक्त ब्याजददेयतावहन करनी पडत्री। इसी प्रकार, परिवहन विभाग को एक्सोग्रे ि िया के रूप में 19 करोड़ रूप्ये की रा ि ा और सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिए 10 करोड़ रूप्ये की रा ि ा भुगतान करना पड़ा। इसके परिमामस्वरूप हमें राज्य योजना के 2091 करोड़ रूपये के मूल परिव्यय को सं ाोधित करके 1850 करोड़ रूपये करना पड़ा। तथापि, निर्धारित क्षेत्रों के अन्तर्गत परिव्यय में कमी नही की गई है।

9. मै माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि हमने राजस्व में अपने साधनों से वृद्धि करने और गैर विकासात्मक खर्च में कमी करने के भरसक प्रयाय किये ह। मै इस गरिमामय सदन को आ वावन देता हूं कि भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से आवंटन किया जायेगा।

कर संग्रह

10. उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार ने मूल्य संवर्द्धन कर (वैट) प्रणाली लागू करने में उल्लेखनीय राजनेतिक इच्छा भाक्ति और साहस का परिचय दिया है, क्योकि दे ा का कोई भ अन्य राज्य ऐसा नही कर सका। वैट प्रणाली एक सर, निश्पक्ष, ज्यादा पारद र्ी व कु ाल प्रणाली है। इससे राज्य सरकार को काफी फायदा हो राह है। चालू वर्श वर्श में दिसम्बर, 2003 तक कर रजस्व, जिसमें बिक्री कर, केन्द्रीय बिक्री कर, स्थानीय क्षेत्र किवास कर तथा मनोरंजन कर की रा ि ा भाामिल है, में 16 प्रति ात की उल्लखनीय वृद्धि होकर यह 2930 करोड़ रूपये हो गया। चालू वर्श में दिसम्बर तक वैंट तथा केन्द्रीय बिक्री कर, प्राप्तियोंमें 358 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई ओर ये 2741 करोड़ यय के स्तर परपहुंच गई। इस अविध में `वल वैट प्रणाली के अन्तर्गत 22 प्रति ात की उल्लखीनय वृद्धि होकर 2126 करोड़ रूपये का कर संग्रह हुआ। राज्य में कर संग्रह मैं वृद्धि न केवल क्षेत्रके अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी अधिक है, बल्कि यह दे ा में उच्चतम वृद्धियों में से एक हैं इसका श्रेय मुख्यतः व्यापारियों और उद्योगपतियों को जात है, जिन्होने वैट प्रणाली अपनाने में काफी उदारता दिखाई जिसके परिणामस्वरूप बेहतर कर अनुपालन सुनि ि चत हुआ और वैट के कारण मूल्यों में कोई वृद्धि नही हुई।

वार्शिक योजना 2004–05

11. उपाध्यक्ष महोदय, राज्य की सामाजिक न्याया के साथ विकास की नीति 2004–05 के लिए 2175 करोड़ रूप्ये के

परिव्य का प्रस्ताव किया है, जो वार्शिक योजना 2003–04 के 1850 करोड़ रूपये के सं ाोधित परिव्यय से 17.6 प्रति ात अधिक है। केन्द्रीय योजना आयोग अपने अन्तिम दौरे के विचार–विम र्ा में इस प्रस्तावित परिव्यय की स्वीकृति प्रदान करेगा। आर्थिक और सामाजिक सेवाओं में आधारभूत संरचना के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। बिजली, सिंचाई, सड़कें और सड़क परिवहन क्षेत्रों की आधारभूत संरचना के विकास के लिए 941.36 करोड़ रूपये का परिव्ययनिर्धारित कियागया है, जो कुल प्रस्तावित परिव्यय का 43.3 प्रति ात है। सड़क ओर सड़क परिवहनको पहली प्राथमिकता दी गई, जिसके लिए 376.20 करोड़ रूपये (17.3 प्रति ात) का परिव्यय निर्धारित किया गया है। बिजली के उत्पादन, सम्प्रेशण और वितरण कोउचित अधिमान दिया गया है,ि जसके लिये 302.16 करोड़ रूपये (13.9 प्रति ात) की रा ि ा उपलब्ध करवाई गई है। सिंचाई क्षेत्र के लिए 263 करोड़ रूपये (12.1 प्रति ात) के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

12.सामाजिक सेवओं की ओर समूचित ध्यान दिया गया है और इनके लिये 919.87 करोड़ रूपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है, जो कुल परिव्यय का 42.3 प्रति ात है। सामाजिक सेवओं में, वयोवृद्ध नागरिकों, विकलांगों, विधवाओं ओर निराश्रित महिलाओं की पें ान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, कयों ये समाज के सर्वाधिक कमजो वर्ग है और राज्य का इनके प्रति नैतिक कर्त्तव्य बनता है। इनके कल्याण के लिय 330 करोड रूपये

(15.2 प्रति ात) के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। महिला एव बाल विकास कार्यक्रमों के लिए 15 करोड़ रूपये की रा ि ा रखीग गई हैं ि ाक्षा तथा तकनीकी ि ाक्षा को 195 करोड़ रूप्ये (9.0 प्रति ात) की रा ि ा उपलब्ध करवाई गई है। जलापूर्ति एवं स्वच्छता के लिए 165 करोडय रूपये (7.6 प्रति ात) की प्रावधान किया गयाहै। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 73.20 करोड रूपये (3.4 प्रति ात) की रा ि ा रखी गई है।

13. प्रदे ा में प्राथमिक ि ाक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवओं, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण आवास, पोशाहार तथा ग्रामीण विद्युतकरण के विस्तार व सुधार के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोंदय योजना के अन्तर्गत 18.34 करोड रूपये की रा ि ा रखी गई। है।

14. उपाध्यक्ष महोदय, वार्शिक योजना 2004–05 के लिए 2175 करोड़ रूपये का परिव्यय प्रस्ताविक कियागया है और हमारीसरकार इन संसाधनों को लोकहित में सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए वचनबद्ध है।

बारहवां वित्त आयोग

15. मै इस गरिमाय सदन को बतान चाहूंगा कि ग्यारवें वित्त आयोग का अवार्ड हरियणा जैसे प्रगति ील राज्यों के लिए कम लाभदायक रहौ आयोग की सिफारि ाों के अनुसार 2000–05 की आधि के दौरान केन्द्रीय करों में हरियाणाका हिसा 1.238

प्रति ात से कम होकर 0.944 प्रतिात रहा गया, जिससेप्रदे ाको 1100 करोड़ रूप्ये कानुकसान हुआ। हमनेआयोग के इस दृश्टिकोण के विरूद्ध सभी केन्द्रीय मंचों पर प्रतिवेदन किया। अब बारहवां वित्त आयेग गठित कर दिया गया है ओर इसकी सिफाारि ें 2005–10 तक मान्य रहेगी। हमने आयोग को प्रस्तुत अपने ज्ञापन में जोर देकर आग्रह किया है कि जनसंख्या, क्षेत्रफल और प्रति व्यक्ति आय के घटकों को ज्यादा अामिान दिया जाना चाहिय ताकि बेहतर वित्तीय प्रबन्धन वाले राज्यों के प्रयासों को पुरस्कृत किया जा सके। इसके अतिरिक्त, हमनेआयोग से आग्रह कियाहै कि वर्श 2005–10 की अवधि के दौरान राज्य को कुल 17865.22 करोड़ रूप्ये का अनुदानदेने की सिफारि ा की जाये ताकि कमी वाले क्षेत्रों में मूलभूत सेवओं के स्तर में सुधार लाया जा सके ओर ाज्य की वि ाश समस्याओं का समुचित समाधान किया जा सकें। इस रा ि ा में मूलभूत सेवाओं के सुधार के लिए 3462.79 करोडय रूपये, वि ोश समस्याओं के समाधान के लिए 6059 करोड़ रूपये ब्याज सबसिडी के रूप में 1538.35 करोड़ रूपये और पूंजीगत परिसम्त्तियों के रख–रखाव के लिये 3784.08 करोड़ रूप्ये की रा ि ा भाामिल है। बारहवां आयोग जब राज्य के दौरे पर आयोग तो हम इन मुद्दों को उसके समक्ष उठायेगें

बिजली

16. राज्य के विकास में बिजली की महत्पूर्ण भूमिका है। इसलिए, हमारी सरकार बिजली क्षेत्र मे ंसर्वाधिक प्राथमिकता दे

रही है। अप्रैल–दिसम्बर 2003 की अवधि के दौरान बिजली की औसत अपलब्धता 53 प्रति ात बढ़कर 561 लाखयूनिट हो गई, जबकि वर्श 1998–99 में यह 367 लाख यूनिट थी। कृशि क्षेत्र को भी अधिक बिजली प्रापत हुई। इस क्षेत्र को प्रतिदिन औसतन 289 लाख यूनिट बिजली सप्लई की गई, जबकि वर्श 1989–99 में ये 367 लाख यूनिट थी। कृशि क्षेत्र को भी अधिक बिजली प्राप्त हुई। इस क्षेत्र को प्रतिदिन औसतन 289 लाख यूनिट बिजली सप्लाई की गई, जबकि वर्श 1989–99 में इसे प्रतिदिन औसतन 184 लख यूनिट बिजली सप्लाई की जाती थी। कृशि क्षेत्र की सप्लाई में यह वृद्धि 57 प्रति ात है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान बिजली की प्रस्थापित क्षमता में 828 मैगावाट की वृद्धि हुई, जेा 1989–99 की बिजली उत्पादन क्षमता के मुकाबले 34 प्रति ात अधिक है।

17. वर्श 2002–03 में राज्य के अपने बिजली उत्पादन स्टे ानों से 6212 मिलिय यूनिट सर्वाधिक उत्पन्न की गई, जकि 1989–99 के दौरान 3784 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया था। बिजली उत्पान में यह वृद्धि 64 प्रति ात से अधिक है। चालू वर्श (अप्रैल–दिसम्बर) के दौरान प्लांट लोड फैक्टर 70.79 प्रति ात रहा, जबकि 1989–899 में 49.24 प्रति ात था यह वृद्धि 21.55 प्रति ात है। साळा ही, तेल खपत, कोयला ातप इत्यादि जेसे अन्य उपलब्धि मापदण्डों में भी उल्लेानिय सुधार हआ है, जिसके फलस्वरूप उत्पादनलागत में काफी कमी हुई है।

18. वर्तमान सरकार ने ताउ देवी लाल थर्मल पावर स्टे ान की सातवी और आठवी यूनिटो का निर्माण कार्य भाुरू किया है, जिससे आगामी वित्त वर्श में प्रतिदिन 100 लाख से अधिक अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होगी। इस परियोजना पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य चल रहा है। अैरइनयूनिओं की क्रम ाः अक्तूबर, 2004 और फरवरी, 2005 में चालू हो जाने की सम्भावना है यमुनानगर ताप बिजली परियोजना का निर्माण कार्य भी निकट भविश्य में भाुरू किया जायेगा। पि चमी यमुना नहर पन बिजली परियोजना चरण– (14.4 मैगावट) का निर्माण कार्य पूराहोने वाला है। साथ ही, राज्य और क्षेत्र से बाहर के स्त्रोतों से अतिरिक्त बिजली जुटाने के लिए बिजली की खरीद की अल्पकालीन और दीर्घकालनी व्यवस्था की जा रही है।

19. वर्तमानसरका के भाासनकाल में 500 करोड़ रूपये से अधिक निवे ा से 71 नये ग्रिड सब–स्टे ान चालू किये गय, 240 सब–स्टे ानों की क्षकता में वृद्धि की गई अङौर 1100 किलोमीटर लम्बी सम्प्रेशण लाईनां की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्तबड़ी संख्याम ें सम्प्रेशण एवं तवरण कार्य निर्माण के विभिन्न चरणों में है, जो आगामी एक वर्श के अन्दर पूरेा हो जायेगे। गत साढ़े चार वर्श के दौरान ट्रांसफार्मरों की क्षमता में 4025 एम0वी0ए0 की रिकार्ड वृद्धि की गई।

20. नलकूपों को बिजली के कनैक्शन भीघ्र जारी करने की आव यकता को समझते हुए गत चार वर्श के दौरान 36000

से अधिक नये नलकूप दिये गये, जबकि इससेपहले प्रतिवर्श औसतन 1000 से भी कम कनपैक ान दिये जात थे। घरेलू तथा गैर–घरेलू कनैक ान जारी करने के लिए वि ोश अभियान भुरू किया गया ताकि आवेदकों को भविश्य में बिना इंतजार किये मांग पर कनैक ान दिये जा सकें।

21. बिजली निगमों के संसाधनों में वृद्धि करने के उद्दे य से हमारी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय प्रतिश्ठानों कोदेय बिजली निगमों की बकाया रा ि ा का भुगतान के लिये एक बारगी निपटाना प्रणाली भुरू की है, जिसे अन्तर्गत 2022 करोड़ रूपये के कर–मुक्त बॉड जारी किये गये है।

22. वर्श 2004–05 के बजट अनुमानों में बिजली क्षेत्र के लिए योजना तथयोजनेतर कुल 1320.42 करोड़ रूपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

जल संसाधन

23. सिचाई का पानी समृद्धि और राज्य की अर्थ व्यवस्था के विकास के लिए कए महत्वपूर्ण घटक है। भूमिगत जल संसाधनों का उपयोग एक सीमा तक ही किया जा सकता है। इसलिये, वर्तमान सरकार जलसंरक्षण और इसक प्रबन्धनपर अधिक बल दे रही हैं उपलब पानी का सिंचाई के लिए सर्वोत्म उपयोग सुनि ि चत करने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं बिजाई मौसम

से पूर्व सिंचाई चैनलों की घास व गाद निकालने का कार्य नियमित रूप से समय पर किया जा रहा है।

24. उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने सिंचाई पानी की पर्याप्त सप्लाईसुनिि चत करने के भरसक प्रयाय किये हैं भाखड़ा जला ाय से पिछले वश्र के मुकाबले इस वर्श ज्यादा नहरी पानी उपलब्ध होने की सम्भावना है। जवाहर लाल नेहरूउठान सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत पानी की सप्लाई में 25 प्रति ज्ञत की वृद्धि हुई है। यमुना नदी के नहरी नेटवर्क की क्षमता में वृद्धि की जा रही है अनेक पुरर्सम्भरण योजनाये भ्रारू की गई है।

25. सिंचाई प्रणाली की तीव्र गति से मरम्मत औ विस्तार की आव यकत को महसूस करते हुए राज्य सरकार आर आई डी एफ के अन्तर्गत नाबर्ड से धन ले रही है। नाबार्ड द्वारा अब तक 708.13 करोड़ रूपयेकी सिंचाई परियोजनाये स्वीकृत की गई ह। जनवरी, 2003 तक नाबार्ड से 312.63 करोड रूपये की सहायता प्राप्त हुई हैं नाबार्ड को 100 करोड़ रूपये की एक नई परियेाजना स्वीकृति के लिये भेजी जा रही है। वर्श 2003–04 के दौरान नाबार्ड से वित्त पोशित सिंचाई परियोजनाओं के लिए 49. 19 करोड़ रूपये के योजनागति परिव्यय की व्यवस्था की गई है और वर्श 2004–05 के लिए 51.50 करोड़ रूप्ये का प्रावधान किया गया है।

26 माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार पंजाब के क्षेत्र में सतलुज–यमुना लिंक (एस वाई एल) नहर का पूरा करवाने के भरसक प्रयाय कर रही है माननीय सर्वोच्च न्यायालयसे अनुरोध कियागया है कि वह इस नहर का भोश कार्य केन्द्रीय जल आयोजन के तकनीकी मार्ग निर्दे ान में भाुरूकरने हेतु सीमासड़क संगठन को मनोनीत करने क केन्द्र सरकार को निर्दे ा दे। पंजाब सरकार को सर्वोच्च न्यायाल द्वारा 17 दिसम्बर, 2003 को निर्दे ा दिये गये कि वह दो सप्ताह के अन्दरअपना जवाब दायरकरे। इस मामल कीसुनवाई भाीघ्र होने की सम्भावना है।

27. बजट अनुमान 2004–05 में सिंचाई क्षेत्र के लिए कुल 734.49 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

सड़के एवं पुल

28. सड़कें आर्थिक विकास के लिए बुनियादी आधारभ्झूतसंरचना हैं इसलिए, वर्तमान सरकार सड़क तंत्र सुधारने, चौडा करने व उसका विस्तार करने परकाफी जोर दे रही हैं जबकिवर्श 1966 में हरियाणा के गठन के समय इनकी लम्बाई 5100 किलोमीअर थी। वर्श 2003–04 के दौरान 2859 किलोमीटर लम्बीसड़कों का सुधार किया गय। हमार वर्श 2004–05 के दौरान 320 करोड़ रूपये के परिव्यय से 163 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों के निर्माण और 2080 किलोमीटर लम्बी सड़कों के सुधार का प्रस्ताव है।

29. माननीय सदस्योंकायह जानकर प्रसन्त्रता होगी कि हमारी सरकारसड़कों के सुधार के लिए नाबार्ड, राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन सी आर) योजना बोर्ड, हुडकों तथा केन्द्र सरकार इत्यादि जैसे सभी यथासम्भव स्त्रोंतो से धनरा ि ा की व्यवस्थाकरती रही है। नाबार्ड ने 60 ग्रामीण सड़कों और 20 पुलों के निर्माण के लिये अगर आई डी एफ-III, IV और VIII के अन्तर्गत 58.99 करोड़ रूपये की परियोजनाये स्वीकृत की है। एक पुल ओर 60 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो गया हैं तथा भोश पुलों पर निर्माण कार्य चल रहा हैं। नाबार्ड द्वारा आर आइ डी एफ-IX के अन्तर्गत सड़कों के सुधार की 160 करोड़ रूप्ये की एक अन्य परियोजना भीघ्र की स्वीकृत किये जाने की सम्भावना है।

30. हुडकों ने 1955 किलोमीटर लम्बे राज्यमागों के सुधार के लिये 415.18 करोड़ रूपये की दो परियोजनाये स्वीकृत की है। कुल 1066 किलोमीटर लम्बे राज्य राजमागों का सुधार किया जा चुका है। और अन्य मोगों पर कार्य चल रहा है। हुडकों द्वारा 325 किलोमीटर लम्बी प्रमुख जिला सड़कों और 7000 किलोमीटर लम्बी अन्य जिला अन्यसडकों के सुधार के लिये भी 285.79 करोड़ रूपये की देा परियोजनाये सवीकृत की गई है। इनपरियोजनाओं के न्तर्गत लगभग 6350 किलोमीटर लम्बी सड़कों का सुधार कया जा चुकाहै। हुडकों की परियेाजनाओं के लिए वर्श 2003–04 तथा 2004–5 के दौरार क्रम ाः 198.88 करोड रूपये और 173.38 करोड़ रूप्ये का परिव्यय रखा गया है। हुडकों की

ऋणों की अदायगी पथ्ज्ञकर से प्राप्त आये सह की जायेगी। प्रदेा में 32 स्थानों पर पथकर लगाया जायेगा, जनमे ंसे 14 स्थानों पर पथकर संग्रह का कार्य भाुरू हो चुका है।

31. राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने भी इन सी आर क्षेत्र में 476.15 किलोमीटर लम्बी 24 सड़कों के सुधार केि लए 63.08 करोड़ रूपये की एक परियोजना स्वीकृत की है, जिसमें से 22.72 करोड़ रूपये की सहायता प्राप्त हो चुकी है।

32. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 1012 किलोमीटर लम्बी सड़कों के सुधार के लिए 107.74 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई हैं केन्द्र सरकार ने वर्श 2003–04 के दौरान 274.51 किलोमीटर लम्ब्र 22 सड़कों के निर्माण के लिए 48.04 करोड़ रूप्ये की सहायता स्वीकृत की है। वर्श 2004–05 के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 378.17 किलोमीटर लम्बी सडत्रकों के सुधार के लिए 81.18 करोड़ रूपये की रा ि ा का प्रावधान हैं

33. राज्य सरकार ने प्रदे ा में महत्पूर्ण पुलों के निर्माण के लिए निर्माण संचालन–हस्तांरण (बी0ओर0टी0) की पद्धति अपनाई हैं कुरूक्षेत्र में वर्तमान सड़क उपरिगामी पुल की दो अतिरिक्त लेनों का निर्माण कायर्रू बी0ओ0टी0 आधार पर जारी है। गुडगांव–फरीदाबाद सड़क का बी0ओ0टीण आधार पर सुधार करने के लिए निविदाये पुनः आमन्त्रित की जा री है। रेलवे द्वारा सड़क उपरिगामी पुलों की लागत की 50 प्रति ात रा ि ा देने के

निर्णय के दृश्टिगत राज्य सरकार ने 182 करोड़ रूपये की लागत के 17 सड़क उपरिगामी पुलों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

34. उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकारने वर्तमान राश्ट्रीय राजमागों के सुधार पर वि ोश बल दिया हैं इस नीति को लागू करने के लिए राज्य में विभिन्न राश्ट्रीय राजमागों की 28.41 किलोमीटर लम्बी सड़कों के सुधार के लए 707.50 लाख रूपये के तीन अनुमान स्वीकृत किये गये हैं ये सभी कार्य चालू वर्श के दौरान पूरे कर लिय जायेगे। इसके अतिरिक्त, चालू वर्श के दौरान राश्ट्रीय राजमार्ग–10 को बहादुरगढ़ से रोहतक तक चारमार्गी बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण का 80 प्रति ात कार्यपूरा कर लिया गया हैं

35. वर्श 2004–05 में सड़क और भवन क्षेत्र के लिए योजना तथा योजनोतर कुल 601.49 करोड़ रूपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया हैं

परिवहन

36. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुदृढ़ अर्थ–व्यवस्था के लिए एक कु ाल सड़क परिवाहन नैटवर्क आव यक है ंयह प्रसन्ता की बात ीहै कि हरियाणा रोडद्धवेज को इसकी संचालन कु ालता और उत्पादकता की दृश्टि से दे ा का सर्वश्रेश्ठ परिवहन सेवओं में से एम काना गया है। इसके बस बेडें में 3431 बसें है।, जो

प्रतिदिन 10.88 लाख किलोमीटर की दूरी तक करती है ओर लगभग 11 लाख यात्रियों को तेज, कु ाल और आरमदायक यात्रा की सुविधा प्रदान करती है। वर्तमान सरकार ने हरियाणा रोडवेज की सेवाओं औरलाभ में सुधार लाने के लिए बस बेड़े का नवीनीकरण व सुधर करने, समय सारिणी और मार्गों के तर्कसंगत बनाने तथा बस सेवाओं में वृद्धि करने जैसे अनेक उपाय किये है। गत तीन वर्शो के दौरान 2044 पुरानी बसां के स्थान पर नई अत्याधुनिक बसें चलाई गई हैं ओर वर्श 2004–05 के दौरान 600 बसों को बदला जायेगा। यह संतोश का विशय है कि इनपुल लागत में बढ़ौतरी के बावजूद वर्श 2002–03 में कर पूर्व लाभ बढ़कर 120.85 करोड यपये होगया, जोकि वर्श 1999–2000 में 26 करोड़ रूपये था सुरक्षा उपायो के परिमणामस्वरूप दुर्घटना दर वर्श 1998–99 में 0.17 प्रति लाख किलोमीअर से कम होकर वर्श 2002–03 में 0.11 रह गई।

37. हमारी सरकार ने हरियाणा से गुजरने वाले चार राश्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात के विनियमन एवं प्रबन्धन के लिए हरियाणा हाईवे पैट्रोल एण्ड रोड सेफ्टी नामक राजमार्गी सुरक्षा संगठन कागठनकरके सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल की है। इसके फलस्वरूप, इन राश्ट्रीय राजमागों पर दुर्घटनाओं में 15 प्रति ात की कमी आई हैं भारतसरकार ने इस मार्गद र्ी प्रयास की सराहना करते हुए अन्य राज्यों को यह प्रणाली अपनाने की सलाह दी है।

38. हमारी सरकार ने संसाधनों में वृद्धि करने और लोगों को कु ाल परिवहन सेवाये उपलब्ध करवाने के लिए एक व्यापाक परिवहननीति भाुरू की है, जिसके तहत 747 मार्गों पर 2073 बस परमिट देने की पे ाक ा की गई हैं फरीदाबाद और गुडगांव भाहरों में बसे संचालन के लिए सिटी बस सेवा नामक एक अन्य योजना भी स्वीकृत की गई हैं हम प्राइवेट ऑपरेटरेां को कान्ट्रैक्ट कैरिज परमिट देने पर भी स्वीकृत की गई हैं हम प्राइवेट ऑपरेटरेां को कान्ट्रैक्ट कैरिज परमिट देने पर भी विचार कर रहे है।

39. बजट अनुमान 2004–05 में परिवहन सेवाओं के लिए कुल 591.69 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

40. लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता रही हैं हरियाणा को अपने प्रत्येक गांव में पेयजल उपलब्ध करवाने का गौरव प्राप्त है। अब हम प्रति व्यक्ति पेयजल आपूर्ति में वृद्धि करने पर ध्यान केन्द्रित कररहे है। हाल ही में किये गयेएक सर्वेक्षण के अनुसार प्रदे ा म ंप्रयेजल की कमी वाले 1829 गांव है, जहां पेयजल आपूर्ति का वर्तमान स्तर 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के स्वीकृत मानदण्ड से कम है।

41. चालू वित्त वर्श के दौरान दिसम्बर तक 237 गांवों मे पेयजल आपूति कास्तर बढ़ाया जा चुका है। वर्श 2004–05 के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति

कार्यक्रम और मरूभूमि कविाकस कार्यक्रम के अन्तर्गत 58.28 करोड़ रूप्ये की लागत से 525 गांवों में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव हैं

42. गांवों की पेयजल आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए नाबार्ड से सहायता ली गई हैं नाबर्ड द्वारा 689 गांवो के लिए 198. 62 करोड़ रूपये की सात परियोजनायें स्वीकृत की गई है। आर0 आई0 डी0 एफ0 योजनाओं के अन्तर्गत चालू वर्श के दौरान 75.45 करोड़ रूपे की रा ि ा और आगामी वर्श के दौरान 77.50 करोड़ की रा ि ा खर्च करने का प्रस्ताव है।

43. माननीय सदस्यगण इस बात की सराहना करेगे कि हरियाणा के सभी भाहरों में नल जल आपूर्ति प्रणाली उपलब्ध है। 31 मार्च, 2003 तक पेयजल आपूर्ति का 75 प्रति ात सेवा स्तर प्राप्त कर लिया गया। चालू वर्श के दौरान पेयजल आपूर्ति का सेवा स्तर 76 प्रति ाततक बढ़ाने के लिए 5.86 करोड़ रूपये की रा ि ा खर्च करने का प्रस्ताव हैं आगामी वर्श के दौरान12.65 करोड़ रूपये की लागत से जल सेवा स्तर 77 प्रति ात तक बढ़ाने का लक्ष्यम है।

44. एन0सी0आर0 योजनाबोर्ड ने सोनीपत, रोहतक, झज्जर, रिवाड़ी और गुडगांव में पेयजल आपूर्ति तथा सीवरेज के सुधार व विस्तार के लिए 71.56 करोड़ रूपये की एक परियोजना स्वीकृत की है। चालू वर्श के दौरान 22.13 करोड़ रूप्ये की रा ि ा

खर्च की जायेगी और आगामी वर्श के लिए 26.13 करोड़ रूप्ये का प्रावधान किया गया हैं एन0सी0आर0 याजनाबोर्ड ने मैगनेट टाऊन–हिसार में पेयजल आपूर्ति और सीवरेज के सुाार व विस्तार के लिए 15.94 करोउ़ रूप्ये की एक अन्य परियोजना भी स्वीकृत की है। केन्द्र सरकार ने अम्बाला सदर, कथैाल और भिवानी भाहरों की पेयजल आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए 49.70 करोड़ रूपये की एक परियोजना स्वीकृत की है। भिवानी भाहर में पेयजल आपूर्ति परियोजना चालू कर दी गई है। और कैथल तथा अम्बाला सदर में कार्य प्रगति पर हैं

45. उपाध्यक्ष महोदय, यमुना कार्य योजना चरण-I के क्रियान्वयन के फलस्वरूप यमुना नही में गिरने वाले गंदे पानी के प्रदूशण स्तर को प्रभावी ढंग से नियन्त्रित कर लिया गया है। केन्द्र सरकार ने इसकी सराहना करते हुए यमुना कार्य योजना चरण-II के अन्तर्गत हरियाणा के लिए 62.50 करोड़ रूपये की एक परियोजना प्र ाासनिक रूप से स्वीकृत कर दी है। ताकि यमुना कार्य योजना चरण-I के अन्तगत आने वाले भाहरों में अतिरिक्त अन्तारेाधन ओर परावर्तन सीवर कार्य किया जा सके। इस पर भीघ्र ही कार्य भाुरू करने का प्रस्ताव है।

46. बजट अनुमान 2004–05 में जन स्वास्थ्य विभाग के लिये कुल 553.20 करोड़ रूपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया हैं

कृशि एवं सम्बन्द्ध गतिविधियां

47. प्रदे ा की 75 प्रति ात जनसंख्या अभी भी कृशि पर निर्भर है ओर राज्य की आय में इसका योगदान 29.4 प्रतिशत है। हमारे लिये यह सर्वोच्च प्राथमिकता का क्षेत्र है। वर्तमानसरकार के ठोस प्रयासों औरकिसानों के कठोर परिश्रम से वर्श 2001–02 के दौरान 132.99 लाख टन खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन हुआ।

48. खरीफ 2002के दौरान राज्य में भंयकर सूखा पड़ा, जिससे कृशि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। परन्तु हमारी सरकार द्वारा पानी, बिजली और अन्य कृशि इनपुट्स का पर्याप्त प्रावधान किये जाने से वर्श 2002–03 के दौरान 123.36 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ। खरीफ 2002 के दौरान गन्ने (गुड़) का उत्पादन 10.70 लाख टन के सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गया।

49. वर्श 2003–04 के दौरान अनुकूल मौसम के कारण खाद्यान्न उत्पादन 137.97 लाख टन होने की सम्भावना है, जो 128.48 लाख टन के लक्ष्य को पार करके अब तक का रिकार्ड उत्पादन होगा। गन्ने (गुड़), कपास और तिलहनों का उत्पादन क्रम ाः 9.82 लाख टन, 13.59 लाख गांठे और 9.83 लाख टन होने का अनुमान है।

50. वर्श 2004–05 के लिए 144 लाख टन खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। गन्ना (गुड़), कपास और तिलहनों का उत्पादन क्रम ाः 9.82 लाख टन, 13.59 लाख गांठे और 9.83

लाख टन, 13.59 लाख गांठे और 9.83 लाख टन होने का अनुमान है।

50. वर्श 2004–05 के लिए 144 लाख टन खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया हैं गन्ना (गुड़), कपास और तिलहनां का उत्पादन लक्ष्य क्रम ाः 10 लाख टन, 15 लाख गांठे और 8.30 लाख टन रखा गया हैं

51. उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार प्रकृति की चुनौतियों के प्रति स्जग हैं कृशि में बेहतर जोखिम प्रबन्धन के उपाय के रूप में हमारी सरकार ने खरीफ 2004 से राश्ट्रीय कृशि बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके अन्तर्गत बाजरा, कपास, मक्का, अरहर, चना और सरसों जैसे उच्च जोखिम वाली फसलें आयेंगी।

52. माननीय सदस्य इस तथ्य से भंली भांति परिचित है। कि वर्तमान फसल पद्धति को बदलने की नितांत आव यकता है। हमें कृशि क्षेत्र में खाद्यान्न देने वाली फसलों की कमी करके उच्च मूलय प्रदान करने वाली फसलें उगानी चाहिये। किसानों को इससम्बन्ध में जागरूक करने के लिए राजय मेंचेतना अभियान भ्ारू किये गये हैंफसलों का विविधिकरण तब तकसफल नही होसकता, जब तक परम्परागत फसलों के स्थान पर बोई जाने वाली अन्य फसलों से किसानों को ऊंची आय सुनि चत नही होती। हमने फसलों के विविधिकरण के लिए एक कार्य योजना बनाई है। और

बारहें वित्ता आयोग से अनुरोध किया है कि वह फसलों के विविधिकरण के कारण किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 960 करोड़ रूपये के अनुदान की सिफारि ा करें।

53. हमारी सरकारने जीरों टिलेज,प्रौद्योगिकी, भूमिगत पानी के सदुपयोग, छिड़काव सिंचाई प्रणाली जैसे विभिन्न किफायती उपाय भ्रुरू किये है। किसानों की सहायता के लिए जिला स्तर पर किसान कस्बों के गठन, हरियाणा कृशि वि ववविद्यालय द्वारा निः ुल्क हैल्पाईन व किसान पुरस्कार जैसी अनेक नई योजनाये भ्रुरू की है।

54. राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने की काफी सम्भावनाये है। राज्य सरकार किसानों को मछली पालन के लिए मत्स्य किसान विकास एजेंसियों के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलबध करवा री हैं वर्श 2002–03 तक मछली उत्पादन बढ़कर 35182 टन हो गया है। राज्य सरकार न वर्श 2003–04 में मछली उत्पादन का लक्ष्य 41500 टन निर्धारित किया। इसके मुकाबले, दिसम्बर, 2003 तक 7658 हैक्टेयर जलीय क्षेत्र को मछली पालन के अन्तर्गत लागर 25900 टन मछली उत्पादन किया गया। वर्श 2004–05 के दौरान 42000 टन मछली उत्पान्न करने और 2100 लाख मछली बीज का भण्डार करने का प्रस्ताव है। भारत सरकार ने राज्य में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए तीन मार्गद र्ी परियोजनाये स्वीकृत की है।

55. ग्रामीण आर्थिक विकास में प ुपाल की महत्वपूर्ण भूमिका हैं हरियाणा में दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रति दिन 656 ग्राम, है, जबकि राश्ट्रीय औसतन 226 ग्राम है। इस समय, राज्य में 2421 प ु संस्थान 110ण्58 लाख प ुधन को चिकित्यासुविधाये उपलबध करवा रहे है। राज्य सरकार ने दुधारू प ुओं के अनुवं िाक सुधार और उनहें रोगमुक्त राने के लिए विभिन्न महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भ ुरू किये है। भैसो, हरियाणा नसल की गायों और बैलों के लिए बीमा योजना भ ुरू करने वाला हरियाणा पहलाराज्य हैं अब तक इस योजना के अन्तर्गत 5764 प ुओं का बीमा किया जा चुका है। हरियाणा प ुधन विकास बोर्ड प ु प्रजनन एवं आनुवं िाक विकास कार्यक्रमों को बढ़ाव दे रहा है। वर्श 2004–05 के लिए 54.72 लाख टन दूध, 14198 लाख अंडें ओर 26.66 लाख किलोग्राम ऊन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। राज्य को प ु रोग मुक्त बनाने के लिए ''मुह–खुर रोग निवारण'' की एक केन्द्रीय परियोजना भ ुरू की गई है।

56. बजट अनुमान 2004–05 में कृशि और सम्बद्ध गतिविधियों के लिए कुल 472.99 करोड़ रूप्ये का प्रावधन किया गया है।

वन

57. उपाध्यक्ष महोदय, वन पर्यावरण का सतुंलन बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र

मेंसे केवल 3.5 प्रति ात भू–भाग पर वन हैं सामाजिक सहयोग से पंचायती भूमि पर वृक्ष लगाये जा रहे है। इसके परिमाणस्वरूप, वर्श 1999 के बाद वन क्षेत्र 790 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। चालू वर्श के दौरान 450 लाखों पौधों के वार्शिक लक्ष्य के मुकाबले दिसम्बर 2003 तक 428 लाख पौधे लगाये जाचुके है। वर्श 2004–05 के दौरान 4.50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित कियागया है। राजय सरकार ने औशधीय पौधों की आर्थिक क्षमता के दृश्टिगत राज्य में इनकी खेती पर वि ोश जोर दिया हैं विभिन्न विभागों के प्रयासों में तालमेल लाने के लिए राज्य औशधीय पौधा बोर्ड गठित किया गया हैं जिन ग्राम पंचायतों के पास 50 एड़ से अधिक भूमि है, उनें कम से कम दस एकड़ क्षेत्र पर औशधीय पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

58. वन्य प्राणियों के बारे में जागरूक पैदा करने के लिए किये जा रहे प्रयासों के अन्तर्गत सरकारने भिण्डावास पक्षी विहार का विकास कार्य भुरू किया है, जांएक नेचर इन्टरप्रेटे ान सैन्टर विकासित किया जा रहा हैं ताक लागों को पक्षियों की विभिनन प्रजातियों औरउनकी किसान हितैशी भूमिका बारे ि ाक्षित किया जा सकें।

सहकारिता

59. सहकारी आंदोलन ने प्रदे ा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं प्रदे ा में 22545 सहकारी समितियों

है, जिनके 47.05 लाख सदस्य है। किसानों की ऋण सम्बन्धी लगभग 75 प्रति ात जरूरतें 19 केन्द्रीय सहकारी बैकों, जिनकी 348 भााखायें और 2423 मिनी बैंक है, के माध्यम से पूरी की जाती है वर्श 2003–04 के दौरान सहकारी संस्थाओं द्वारा 4100 करोड़ रूपये के अल्पावधि ऋण और 221.30 करोड़ रूपये के दीर्घावधि ऋण वितरित किये जायेगे।

60. राज्य में सहकारी चीनी मिलें संतोशजनक ढंग सेकाय्र कर रही है। चालू वर्श के दौरान सहकारीचीनी मिलेां को गन्ने के भुगतान के लिए 130 करोड़ रूप्ये की बजट सहायता उपलब्ध करवाई गई। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि राज्य की पांच सहकारी चीनी मिलों ने तकनीकी कु ालता और गन्ना विकास के लिए पांच राश्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किये हैं

61. बजट अनुमान 2004–05 में सहकारी क्षेत्र के लिये योजना और योजनेतर 34.49 करोड़ यपये के परिव्यय का प्रावधान किय गया हैं

खाद्य एवं आपूर्ति

62. माननीय सदस्यों को ज्ञात हैं कि खाद्यान्नों के मामले में हरियाणा एक बहुधान्यक प्रदे ा है ओर केन्द्रीय अन्न भण्डार को अनाज देने वाला दे ा कादूसरा सबसे बड़ा राज्य हैं केन्द्रीय अन्न भण्डार में हमारे राज्य का योगदान 30 प्रति ात औरचावल का योगदान 8 प्रति ात हैं न्यूनतम समर्थन मूलय की

वर्तमान प्रणाली किसानों को लाभदायक मूल्या सुनि ित करने का एक कारगार साधन रही हैं खरीफ 2003–04 के दौरान 23.39 लाख मीट्रि टन लेवी धान को खरीद की गई, जिसमें से केन्द्रीय अन्न भण्डारको 13.50 लाख मीट्रिक टन चावल दिया जायेगा। रबी 2003–04 में केन्द्रीय अन्न भण्डार के लिए 51.22 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरी की गई। रबी 2004–05 के लिए 342 मण्डियों के नेटवर्क के माध्यम से 65 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की गई। बाजराउत्पादक क्षेत्रों के किसानों को इस उपास से काफी रहात मिली हैं वर्तमान सरकार मण्डियों में अने वाले किसानों के समस्त गेहूं, धान और अन्य अनाजों की खरीद करने ` लिए वचनबद्ध है।

औद्योगिक विकास

63. उपाध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा औद्योगिक रूप से विकसित राजयों में से एक है ओर यह अपनी सर्वोत्तम आधारभूत संरचना, बेहतर कानून व्यवस्था और उद्योगपतियेां और श्रमिकों के बीच अच्छे सम्बन्धेां के कारण दे ाी तथा विदे ाी निवे कों की प्रथम पसन्द के रूप में उभरा है। इसके फलस्वरूप वर्तमान सरकार के भाासनकाल में 198 नये बड़े तथा मध्यम स्तर के उद्योग और 4500/– लघु उद्योग स्थापित हुए है।

64. राज्य सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए एक व्यावहारिक नीति अपनाई हैं राज्य की नई उद्योग नीति का मुख्य

उद्दे य सहायम नीतियों के साथ–साथ उन्नत्र बुनिादी ढांचा उपलबध करवाकर निवे ा के अनुकूल वातावरण पैदा करना है। गत लगभग चार वर्श के दौरान हमारे मुख्यमंत्री के अनथक प्रयासों की बदौलत प्रदे ा में 10000 करोड़ प्ये का अतिरिक्त निवे ा हुआ, जिससे दो लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए। अत्याधुनिक औद्योगिक सम्पदाये विकसित करने के हमारे प्रयासों से 6500 एकड़ क्षेत्र काएक भूमि बैक स्थापित हुआ हैं हमारी उदार औद्योगिक नीति के कारण हुडा ओरएच0 एस0 आई0 डी0 सी0 ने जुलाई, 1999 से दिसम्बर, 2003 तक की अवधि के दौरान 6.128 औद्योगिक प्लाट आबंटिक यि हैं विदे ी निवे ा आकर्शित करने` लिए वैद ी निवे ा प्रोत्साहन बोर्ड भी गठित किया गया है।

65. माननीय सदस्यगण इस बात की प्र ांसा करेगे कि हरियाणा राज्य औद्योगिक उद्यम ज्ञापनों के क्रियान्वयन में 37 प्रति ात की अखिल भारतीय औसत के मुकाबले 59 प्रति ात औसत के साथ दे ा का प्रथम राजय बन गया है। नवम्बर, 2003 तक 33535 करोड़ रूपये के निवे ा के 2984 औद्योगिक उद्यम ज्ञापन प्रस्तुत किये गये, जिनमें से 1782 ज्ञापन क्रियान्वित किये जा चुके है। हमारी सरकार के भाासनकाल में 7306 करोड़ प्ये के पूंजीगत निवे ा के 759 औद्योगिक उद्यम ज्ञापन क्रियान्वित किये गये है।

66. बेहतर आधारभूत संरचनाओं और व्यापार व उद्योग को दिये गये प्रोत्साहनों के कारण राज्य का निर्यात गत वर्श 10000 करोड़ रूपये के आंकड़े को पार कर गया। चालू वर्श के दौरान निर्यात बढ़कर 12000 करोड़ रूपये हो जाने की सम्भावना है। राज्य सरकार निर्यात और प्रत्यक्ष विदे ाी निवे ा को बढ़ावा देने के लिए जिला गुडगांव के गांव गढत्री हरसरू में 3000 एकड़ क्षेत्र में एक वि ोश आर्थिक जोन स्थापित कर रही है।

67. हरियाणा निवे ाकों, वि ोशतः विदे ाी निवे ाकों की पहली पसन्द बन गया हैं वर्तमान सरकार के भाासनकाल के दौरान 3132 करोड़ रूप्ये के निवे ा से एक पैट्रो कैमिकल कॉम्पलैकस भी स्थापित कर रहा हैं

69. बजट अनुमान 2004–05 में औद्योगिक विकास के लिए योजना और योजनोतर कुल 79.44 करोड़ रूपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

व्यावसायिक ि ाक्षा एवं रोजगार

70. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार उद्योग तथा व्यापार की आव यकता को पूरा करने और स्व–रोजगार को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी ि ाक्षा के विकास को अत्यधिक महत्व देती है। वर्तमान तथा नये ि ाक्षा संस्थानों में सुविधाओं की गुणवता में सुधार व उन्नत्र पर वि ोश बल दिया जा रहा है।

71. औद्योगिक प्र ि ाक्षण एवं व्यावसायिक ि ाक्षा विभाग समस्त राज्य में 195 संस्थानों के तन्त्र, जिसमें 80 औद्योगिक प्र ि ाक्षण संस्थान और 115 व्यावसायिक ि ाक्षा संस्थान भाामिल है, के माध्यम से लगभग 31000 छात्रों को सटिफिकेट कोर्स की ि ाक्षा प्रदान कर रह है। इनमें से 31 संस्थान केवल महिलाओ के लिए हैं लोहारू में व्यावसायिक ि ाक्षा संस्थान का भवन पूरा हो गाय हैं और चौटाला तथा गन्नौर में औद्योगिक प्र ि ाक्षण संस्थानों के भवनों तथा पंचकूला और टांकड़ी में व्यावसयिक ि ाक्षा संस्थानों के भ्ज्ञवनों का निर्माण प्रगति पर है। वर्श 2004–05 के दौरान कालाली–बलाली और बांडा हेड़ी में व्यावसायिक ि ाक्षा संसस्थानों के भवनों का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

72. तकनीकी ि ाक्षा का विस्तार करने और प्रत्येक जिले में एक बहुतकनीकी संस्थान स्थापित करने ` लिए लिये निजी क्षेत्र को इंजीनियरिंग कॉलेज और बहुततकनीकी संस्थान स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा में परिणामास्वरूप, डिग्री और डिप्लोमा स्तरीय संसथानों की संख्या 1999 में 58 से बढ़कर वर्श 2003–04 में 117 हो गई है और सीटों की संख्या भी 9308 से बढ़कर 20977 हो गई है। चारसंस्थानों में इंजीनियरिंग ओर प्रौद्योगिकी की स्नातकोत्र कक्षाओं भ्ारू करने पर वि ोश बल दिया गया हैं जिला सिरसा के गांव पन्नीवाला मोटामें भौक्षणिक सत्र 2003–04 से चौ० देवी लाल मैमोरियल इंजीनियकरिंग के नाम

से एक नया कालेज भाुरू किया गया है, जेा 240 सीटों केसाथ इंजीनियरिंग की चार भााखाओं में ि ाक्षा प्रदान कर रहा हैं तकनीकी ि ाक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाकर भौक्षणिक उत्कृश्टता को बढ़ाव देने के लिए 19.36 करोड़ रूपये की वि व बैक से सहायता प्राप्त तकनीकी ि ाक्षा गुणवता सुधार परियोजना स्वीकृत की गई है।

ि ाक्षा

73. स्कूली सुविधाओं के विस्तार और ि ाक्षा में सुधार के साथ सबके लिए प्राथमिक ि ाक्षा सुनि ि चत करना, राज्य सरकार की प्राथमिकता का प्रमुख क्षेत्र रहा है। उच्चकोटि की ि ाक्षा मानव संस्थान विकास के लिऐ अति आव यक हैं इस तथ्य के दृश्टिगत हमारी सरकार 6 से 11 वर्श की आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूलों में दाखिला करने के भरसक प्रयार कर रही हैं ताकि प्राथमिक ि ाक्षा को सर्वव्यापी बनाने के उद्दे य को प्राप्त किया जासके। हराज्यम ं अब 1.11 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक स्कूल की सुविधाये उपलब्ध है। इस समय राज्य में 11500 राजकीय प्राथमिक स्कूल है। हमार ीसरकार ने स्थानीय समुदाय ओर ग्राम पंचायतों के सक्रिय सहयोग से वि ोश दाखिले अभियान भाुरू किये है। लोगों में ि ाक्षा की आव यकता और इसके महत्व के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किय जाता हैं बच्चों को स्कूलों में दाखिल करने और उन्हें अपनी पढ़ाई बची में

अधूरी न छोड़ने के लिए प्रेरित करने हेतु मुफ्त वर्दी एवं लेखन सामग्री, उपस्थिति पुरस्कार, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें और वि ोश उपस्थिति भत्ते जैसे वि ोश प्रोत्साहन भ्रारू किये गये हैं प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की कुल संख्या 19.72 लाख है।

(इस समय माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

74. वर्तमान सरकार केन्द्र सरकार की भागीदारी से सर्वि ाक्षा अभियान की योजना को क्रियान्वित करने के लिए वचनबद्ध हैं यह योजना वर्श 2007 तक प्राथमिक ि ाक्षा को सार्वभौमिक बनाने, वर्श 2010 तक आठ वर्श तक की स्कूली ि ाक्षा सुनि ि चत करने तथा वर्श 2003 तक स्कूलों में सभी बच्चों के दखिले सुनि ि ाचत करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक बहुआयामी योजना है। यह योजना राज्य के सभी 19 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है।

75. हमारी सरकार उच्चतर ि ाक्षा को वित्तीय दृश्टि से आत्मनिर्भर बनाने की आव यकता के प्रति सजग है। चालू वर्श के दौरान रोजगारेन्मुखी क्षेत्रों में उच्चतर ि ाक्षा को बढ़ावा देने के लिए 23 सहायता प्राप्त प्राइवेट कॉलेजों को स्व–वित्त व्यवस्था आधार पर नये कोर्स भ्रारू करने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार ने प्रदे ा में छः ि ाक्षा समितियों को बी0एड0, विधि और डिग्री कक्षायें संचालित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये है।

76. माननीय सदस्यों को यह जानकार प्रसन्नता होगी कि हमारी सरकार ने वर्श 2003–04 के दौरान भौक्षणिक दृश्टि से पिछड़े क्षेत्र, सिरसा में चौ० देवी लाल वि ववि्यालय स्थापित किया है। इस वि ववि्यालय के स्थापित हो जाने से हजारों वि्यार्थियों को लाभ हुआ है। वर्श 2003–04 के दौरान इस वि ववि्यालय मको 15 करोड़ की रा ि ा उपलब्ध करवाई गई है।

77. बजट अनुमान 2004–05 में ि ाक्षा क्षेत्र के लिए योजना औरयोजनेतर कुल 1938.56 करोड़ रूपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है, जिसमें प्राथमिक ि ाक्षा के लिये 951.20 करोड़ रूपये, माध्यमिक ि ाक्षा के लिए 6060.01 करोड़ रूपये, उच्चतर ि ाक्षा के लिये 245.20 करोड़ रूपये तकनीकी ि ाक्षा के लिए 52.23 करोड़ रूपये, औद्योगिक प्र ि ाक्षण के लिए 51.61 करोड़ रूप्ये तथा कला, सांस्कृतिक एवं युवा कल्याण गतिविधियों के लिए 32.31 करोड़ रूपये भाामिल है।

खेल एवं युवा कल्याण

78. वर्तमान सरकार खेालों के विकास तथा बुनियादी आधारभ्ज्ञूत संरचना के निर्माण पर वि ोश ध्यान दे रही हैं जिसके फलस्वरूप हरियाणा में उत्कृश्ट खिलाड़ी पैदा करके खेल के क्षेत्र में अपनी वि ि ा ट पहचान बना ली है। हमारीसरकार ने राश्ट्रीय तथा अन्तर्राश्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृश्टता लाने के लिए एक खेल नीति बनाइ है, जो दे ा में अनूठी हैं

79. वर्श 2003 के दौरान हरियाणा के खिलाड़ियों का प्रद र्ान उत्कृश्ट रहा है। हैदराबाद में हुए एफ्रो–ऐि ायन खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों, जो विभिन्न खेलो की भारतीय टीम के सदस्य थे, ने 10 स्वर्ण, एक रजत औरएक कांस्य पदक प्राप्त किया। ये उपलब्धियों हमारी प्रगति ील खेल नीति के कारण सम्भव हो पाई हैं

80. वर्श 2003–04 के दौरान 445 खिलाड़ियों को 161. 46 लाख रूपये के नकद पुरस्कार दिये गये। किसी खेल प्रतियोगिता के दौरान किसी खिलाड़ी की दुर्घटनाव ा मृत्यु होने अथवा चोट पहुंचने पर उसके परिवार को पांच लाख रूपये तक वित्तीय सहायता देने की एक नई योजना भाुरू की गई है। उत्कृश्ट खिलाड़ियों का भविश्य सुनिि चत करने के लिए खिलाड़ियों को भर्ती करके, जिनका दर्जा नियमित सरकारी कर्मचारियों काहोग, 13 खेलों की टीमें तैयार की जा रही है। गुड़गांव में 2.35 करोड़ रूपये की लाग5 से राज्य का पहला हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्थापित किया गया है और वर्श 2004–05 के दौरान भााहाबाद में ऐसा दूसरा एस्ट्रोटर्फ स्थापित कर दिया जायेगा। राज्य सरकार वर्श 2004 में एथेन्स में होने वाले ओलम्पिक खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले हरियाणा के प्रत्येक खिलाड़ी को एक करोड़ रूप्ये का नकद पुरस्कार देने की अपीन प्रतिबद्धता पर कायम है।

समाज कल्याण

81. अध्यक्ष महोदय, जननायक चौ० देवी लाल दलितों, बुजुर्गों, विधवाओं, विकलागों और समाज के अन्य वंचित वर्गों के मसीहा थे। वर्तमान सरकार ने उनके स्वप्नों को साकार करने के लिए समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। समाज के कमजोर वर्गों, जैसे कि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों का सामाजिक आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाये चलाई जा रही है बढ़ी हुई वृद्धावस्था पें ान तथा विकंलाक पें ान की योजनाये जारी हैं पें ान के लिए चालू वर्श में 310.47 करोड़ रूप्ये तथा आगामी वर्श में 340.07 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया हैं बुजुर्गों के कल्याण के उपास के रूप में प्रदे ा में 606 ताऊ देवी लाल वृद्ध विश्राम गृहों का निर्माण किया जा चुका है। ओर 356 निर्माणधीन है।

82. माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्तमान सरकार ने 2 अक्तूबर, 2003 से चौ० देवी लाल जन सुरक्षा बीमा योजना (देवीराक्षक) नामक एक नई योजना भारू की है, जिसके अन्तर्गत किसी परिवार के 18 से 80 वर्श के आयु वर्ग के कमाऊ सदस्य की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाने परउस परिवार को एक लाख रूपये का मुआवजा दिया जायेगा। अपंगता की स्थिति में उसकी अपंगता के आधार पर 25000 रूपये से एक लाख रूपये तक की रा ि ा मुआवजें के रूप में दी जायेगी। इस उपास से भाोक संतप्त परिवार को रहात मिलेगी। परिवार लाभ

योजना के अन्तर्गत भी प्रमुख कमाऊ सदस्य की मृत्यु की स्थिति में परिवार को 10000 रूपये की राहत उपलब्ध करवाई जा रही है।

83. राज्य सरकार अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का सामाजिक, आर्थिक तथा भौक्षणिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाये क्रियान्वित कर रही हैं कन्यादान योजना का सं ाोधित करके इसका विस्तार कियागया है। अब इस योजना के अन्तर्गत 5100 रूपये की वित्तीय लाभ गरीबी रेखाके नीचे जीवन यापना करने वाले समाज के सभी वर्गों को मिलेगा। इस योजना के तहत दिसम्बर, 2003 तक 19695 लाभानुभोगियों को 10.04 करोड़ रूपये की रा ि ा वितरित की गई। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों के बस्तियों में सुधार लाने के लिए भी अनेक योजनाये क्रियान्वित की जा रही है।

84. वर्तमान सरकार मानव संसाधन विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। महिलाओं और बच्चों के विकास तका स ाक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनायें क्रियान्वित की जा रही है। प्रदे ा के 111 ग्रामीण और पांच भाहरी विकास खण्डों में 13546 आंगनवालड़ी केन्द्रों के ामध्यम से समेमित बाल विकास योजना क्रियान्वित की जा रही है।, जिसक अन्तर्गत 8.84 लाख बच्चों तथा 2.30 लख गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं को अनुपूरक पोशहारउपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्श 2004–05 के दौरान 11.48 लाख लाभानुभोगियों को इस योजना के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव हैं प्रदे ा की 16324 कि ाोरियों को

पूरक पोशहार उपलब्ध करवाने और 19608 लड़कियों की छखता में सुधार करने के उद्दे य से 85 समेकित बाल विकास परियोजना क्षेत्रों में कि ाोरी भाक्ति येाजना क्रियान्वित की जा रही है। इसी प्रकार, लड़कियों के प्रति सामाजिक दृश्टिकोध बदलने के लए बालिका समृद्धि योजना भी चलाई जा रही है, जिससे 4486 लड़कियों को लाभ हुआ है।

85. हमारी सरकार दे ा की सीमाओं की रक्षा करने वाले भूरवीर सैनिकों के कल्याण के प्रति भी सजग है। भूतपूर्वक सैनिकों/विधवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में विभिन्न प्रोत्साहन योजनायें क्रियान्वित की जा रही है।

86. बजट अनुमान 2004–05 में समाज कल्याण योजनाओं के लिए कुल 558.96 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य सेवाए

87. वर्तमान सरकार राज्य के लोगों का स्वास्थ्य स्तर ऊंचा उठाने के लिए वचनबद्ध है। इस समय राज्य में 50 अस्पतालों, 64 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 404 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो, 2299 उपकेन्द्रों, 12 जिला तपेदिक केन्द्रों और 55 औशद्यालयों के माध्यम से लोगों को उच्चकोटि की स्वास्थ्य सुविधाये उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त, पी0जी0आई0एम0एस0 रोहतक तथा मैडिकल कॉलेज, अग्रोहा द्वारा

भी लोगों को वि ोशज्ञ स्वास्थ्य सेवाये उपलबध करवाई जा रही है।

88. राज्य सरकार स्वास्थ्य केन्द्रों में समुचित सुविधाये उपलब्ध करवाने के भरसक प्रयास कर रही हैं वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद 44 स्वास्थ्य संसथानों के नये भवन पूरे किये गये है ओर 39 संस्थानों के भवर निर्माणधीन है, जबकि 20 और भवनों की आधारि ाला रखी गई है। इसके अतिरिक्त राज्य में चिकित्या केन्द्रों को आधुनिक उपलकरणों और उच्चकोटि की दवाईयों से सुसज्जित किया गया है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर में सुधार लाया जा सकें।

89. माननीय सदस्यों को यह जानकार प्रसन्नता होगी कि हमारे मुख्यमंत्री ने पहली नवम्बर, 2003 से स्वास्थ्य आपके द्वारा नामक एक नई योजना भुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत रक्त की कमी, तपेदिक, यौन रोग, नेत्र इत्यादि से सम्बन्धित रोगों की पहचान के लिए सभी नागररिकों के स्वास्थ्य की उनके घरद्वारा पर जांच की जायेगी। 15 जनवरी से 15 फरवरी, 2004 तक स्वास्थ्य जागरूकता माह मनाया जा रहा है। इस अवधि के दौरान राज्य के सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में तीन दिवसीय स्वास्थ्य मेले आयोजित किये जा रहे है।

90. मै माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि 2001 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में एक हजार पुरूशों के पीछे

861 महिलाये है ओर यह अनुपात 933 के अखिल भारतीय अनुपात के मुकाबले न्यूनतम है। इससे लिंगानुपात में असंतुलन पैदा हो गया है। इस असंतुलन को ठीक करने के लए प्रदे ा में 24 नवम्बर, 2003 से सं ाोधित देवीरूपक योजना लागू की गई है। अब दम्पतियों को पूर्व सं ाोधित योजना के अन्तर्गत उपलब्ध वित्तीय लाभ सबसे छोटा बच्चा पांच वर्श का होने से पूर्व परिवार नियोजन के स्थाई उपाय अपनाये जाने पर पुरूश के लिए 45 वर्श की आयु तक और महिलाओं के लिए 40 वर्श की आयु तक उपलब्ध होगे। अब तक इस योजना के अन्तर्गत 3915 दम्पतियों का पंजीकरण किया जा चुका है। जिनमें से 181 दम्पतियों ने बंध्यकरण आप्रे ान करवा लिए है। येाजना आयोग ने इस योजन ने इस योजना की काफी सराहना की है।

91. राज्य में अगस्त, 2003 से एक स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया है, जिसके अन्तर्गत सैकेण्डरी कक्षाओं तक के सभी स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जां की जा रही है। अब तक लगभग 11 लाख बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई है ओरउनहें उपचार दिया गया है।

92. राज्य सरकार ने पोलियों उन्मूलन के लिए एक वि ोश अभियान भाुरू किया है।वर्श 2003–04 के दौरान पत्लस पोलियों के चार उप राश्ट्रीय अभियान चलाये गये हैं जनवरी, 2004 में इस कार्यक्रम के राश्ट्रीय अभियान के अर्न्तत 3820890 बच्चों को पोलियों ड्रॉप्स पिलाये गये।

93. राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं, वि ोशतः महिलाओं और बच्चों की सेवाओं मे सुधार लाने के लिए यूरोपियन आयोग द्वारा वित्त पोशित सैक्टर निवे ा कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। और यह विभिन्न चरणों में अन्य जिलों में भी लागू किया जायेगा। सं ाोधित तपेदिक नियन्त्रण कार्यक्रम, जो इस समय राज्य के पांच जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है, से उपचार दस बढ़कर 81 प्रति ात हो गइ है और ''डिफाल्ट रेट'' कम होगर 12 प्रति ात रह गई है। हरियाणा एड्स नियन्त्रण सोसाइटी ने पी0जी0आई0एम0एस0 रोहतक में एक तथा अन्य 12 सिविल अस्पतालों में स्वैच्छिक पराम र्ा तथ जांच केन्द्र स्थापित किये है। राज्य के सभी जिालें में ऐसे केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

94. बजट अनुमान 2004–05 में मैडिकल ि ाक्षा और वैकल्पिक चिकित्या पद्धति समेत स्वास्थ्य सेवाओं के लिये योजना औरयोनेतर 406.72 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण विकास पंचायत

95. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन और रोजगार के अवसर जुटाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए, हमारी मुख्य नीति ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी आधारभूत संरचना का निर्माण करने ओरउसका सुधार करने की रही है। राज्य सरकार केन्द्र द्वारा प्रयायोजित ग्रामीण विकास के सभी कार्यक्रमों को लागू करने के लिए प्रतिबढद्ध है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व–रोजगार

योजना के अन्तर्गत दिस्म्बर, 2003 तक 793.63 लाख रूपये की रा ि ा खर्च की गई, जिससे 6731 व्यक्तियों को लाभ हुआ, जिसमें 3054 अनुसूचित जातियों के व्यक्ति ओर 4005 महिलाये भाामिल है। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2003 तक 48.40 लाख श्रम दिवस जुटाने के लिए 4719.37 लाख रूपये की रा ि ा खर्च की गई और दिहाड़ीदारों को 39632 मीट्रिक टन गेहूं वितरित कया गया। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण व्यक्तियेां की आवास सम्बन्धी जरूरतों को पूराकरने के लिए इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत व्यक्तियों को आवास सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2003 के अन्त तक 1213.90 लाख रूपये की लागत से 4893 मकानों को निर्माण कार्य पूरा किया गया और 1972 मकान निर्माणधीन है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2003 तक 56.48 लाख रूपये की लागत से 258 मकान निर्मित किये गये है। मरूस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर, 2003 तक वाटर भौड परियोजनाओं की विभिन्न गतिविधियों पर 1984.32 लाख रूपये की रा ि ा खर्च की गई।

96. निचले स्तर पर सत्ता का विकेन्द्रीयकरा करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को अनेक प्र ाासनिक और वित्तीय अधिकार दिये गये है ताकि वे विकास प्रक्रिया में अपना योगदार दे सकें ओर प्रजातांत्रिक प्रणाली सुदृढ़ हो सके। लगभग सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास समितियों गठित की गई है। प्राथमिक

स्कूलों का प्र ाासनिक नियन्त्रण पंचयाती राज संस्थाअें को दिया गया है। राज्य सरकार ने इस संस्थाओं को चालू वर्श से सामान्य बजट सहायता के अतिरिक्त स्थानीय क्षेत्र विकास कर से प्राप्त होने वाली आय में से भी उनके हिस्से की रा ि ा हस्तांरित करने का निर्णय लिया है। ताकि यह रा ि ा विकास कार्यो पर खर्च की जा सकें।

97. बजट अनुमान 2004–05 में विभिनन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए कुल 130.52 करोड़ रूप्ये का प्रावधान किया गया है।

सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम

98. हरियाणा ने सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के माध्यम से प्र ाासन को लोगों के घरद्वार पर ले जाने में पहल की है। यह कार्यक्रम न केवल राज्य में, अपितु दे ा में काफी लोकप्रिय हो गया है। राज्य के लोग जब विकास कार्यो के लिए मुख्यमंत्री के साथ सीधे बातचीत करते है, तेा वे गर्व महसूस करते है। अब राज्य में इस कार्यक्रम का चौथा चरा भ्ारू हो गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत घोशित किये गये विकास कार्यो के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास कोश तथा हरियाणा राज्य कृशि विपणन बोर्ड के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के अन्तर्गत 28822 विकास कार्य पूरे किये जा चुके है

ओर 14393 पर काम चल रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1891. 10 करोड़ रूप्ये की रा ि ा खर्च की जा चुकी है।

नगरपालिका प्र ाासन और नगर विकास

99. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार भाहरी क्षेत्रों में रहनेवाले लोगों के समेकित कल्याण के प्रति भी उतनी ही चिंतित है ओरउकने लिए सर्वोत्मम नगरपालिका सेवाये तथा नागरिक सुविधाये सुनि ि चत करने के लिए वचनबद्ध है। इस समय 68 स्थानीय निकाय, जिनमें एक नगर निगम, 21 नगर परिशदें और 46 नगरपालिकाए भाामिल है।, भाहरों में ये सेवाये उपलब्ध करवा रहे है। भाहरी स्थानीय निकार्यो को विभिन्न योजनाओं अर्थात भाहरी मलिन बस्तियेां के पर्यावरण सुधार, राश्ट्रीय मलि बस्ती सुधार कार्यक्रम, छोटे और मध्यम भाहरों के समेकित विकास, भाहरी ठोस कचरा प्रबन्धन इत्यादि के ामध्ये से वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त, ग्यारवे वित्ता आयोग के अवार्ड के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रीय सहायता भी इन निकायों को उपलब्ध करवाई जारही हैं नगर विकास विभाग ने भाहरी क्षेत्रों के सुधार के लिए भारत सरकार के सथएक समझाौते पर हस्ताक्षर किये है, जिसके अन्तर्गत चालू वर्श और आगामी वर्श के लिए 10.70 करोड़ रूपये प्रतिवर्श की केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई है। स्थानीय क्षेत्र विकास कर से प्राप्त आय में से स्थानीय निकायों के हिस्से की रा ि ा भी नगर विकास कार्यो के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य सरकार नइे इन

निकायों के लिए राज्य संसाधन हस्तातरित करने के तौर–तरीके सुझाने हेतु द्वितीय राज्य वित्त आयोग गठित कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा आयोग की रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद इननिकायों को वित्तीय अन्तरण कर दिये जायेगे।

100. हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण (हुड्डा) लोगों को रहने के लिए बेहतर पर्यावरण उपलब्ध करवाने और विभिन्न सामाजिक व वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए भूमि सम्बन्धी जरूरत को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। हुडा ने चालू वर्श के दौरान 7055 आवासीय प्लॉट और 1084 औद्योगिक प्लॉट बिक्री के लिए पे ा किया और नवम्बर, 2003 तक भाहरी सम्पदाओं में संरचानतम्क सुविधाओं के विकास पर 203.24 करोड़ रूपये की रा ि ा खर्च की। ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय कालोनियों के विकास के लिए नियोजित ग्राम योजना नमाक एक नई योजना भ्ारू की गई है।

101. बजट अनुमान 2004–05 में नगरविकास के लिए 60.23 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

इलैक्ट्रॉनिक प्र ाासन–एक नई पहल

102. सूचन प्रौद्योगिकी (आई0टी0) समाज के सामाजिक आर्थिक विकासक ` लिए एक प्रमुख घटक है। हमारी सरकार ने आई0टी0 से सम्बद्ध उद्योगों के लिए बुनियादी संरचना के विकास के सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। संचार तंत्र की आधारभूत संरचना

का ओर अधिक विकास करने के लिए एक मार्गाधिकार नीति बनाई गई है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारने चार कम्पनियों के सथ समझौते किये हैं आई0टी0 उद्योग को एकल खिड़की सेवा उपलब्ध करवाने के लिए गुडगांव में एक खेत्री आई0टी0 उद्योग प्रोत्साहन कार्यालय स्थापित किया गया है। उन्नत आई0टी0 आधारभूत संरचना के परिणामस्वरूप वर्श 2002–03 के दौरान हरियाणा का साफ्टवेयर निर्यात 4450 करोड़ रूपये हो गया, जो राज्य के कुल निर्यात का 45 प्रति ात है। राज्य सरकार ने प्रदे ा में साईबर पार्क औरसाईबर सिटी स्थापित करन के लिए मानदण्ड़ों को भी उदार बनाया गहै। गुडगांव में 78 एकड़ क्षेत्र पर साईबर सिटी की स्थापना के लिए लाईसैस जारी किया गया है। ताकि वहां आई0टी0 से सम्बद्ध उद्योग स्थापित किये जा सके। प्रदे ा की 104 तहसीलों/उप तहसीलों में हरियाणा राज्स्व दस्तावेज पंजीकरण सूचना प्रणाली क्रियान्वित की जा रही है।

वित्तीय प्रबन्धन

103. अध्यक्ष महोदय, वित्तीय प्रबन्धन समग्र राज्य प्र ाासन का एक अभिन्न अंग है। हाल के वर्शो में केन्द्र स्तर पर नीतियों परिवर्तनों और राज्य स्तर पर किवास की प्रतिबद्धताओं की वजह से राज्य की वित्तीय स्थिति पर काफी दबाव पड़ा। राज्य प्र ाासन, पैं ानों व ब्याज भुगतान के बढ़ते खर्च तथा सार्वजनिक ऋण भार चिन्ता के विशय है, जिनके प्रति राज्य सरकार सजग है। तथा उचित प्रयास कर रही है।

104. वर्तमान सरकार ने वित्तीय सुधारों की आ यकता को महसूस करते हुए वित्तीस पुनर्गठन के अनेक उपाय किये है ंसरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति ठानों के प्र ाासनिक ढांचे और अमला पद्धति को तर्कसंगत बनाने के लिए कदम उठाये गय है।

105. अध्यक्ष महोदय, हमने राजस्व में वृद्धि करने, खर्च में कमी करने ओर ऋण प्रबन्धन की एक संयुक्त नीति अपनाई है। हमने करों के बेहतर अनुपाल के लिए अपने करप्र ाासन में प्रमुख सुधार करके नियमों, प्रक्रियों व कर–दरों को तर्कसंगत बनाया है। हरियाणा दे ा का पहलना राज्य है, जिसमें मूलय संवर्द्धन कर (वैट) की सर्वाधिक पारद र्ाी तथा कु ाल प्रणाली अपनाई है ज्यादा कर संग्रह के रूप में इस प्रणाली के स्पश्ट परिणाम सामने आये हैं

106. मैने अपने पिछले बजट भाशण में ऋण देयताओं को पूरा करने के लिए ऋण निवारण कोश के गठन का उल्लेख किया था। हमने भारतीय रिजर्व बैक की स्वीकृति उपरान्त समेकित ऋण निवारण कोश तथा गारंटी विमोचन कोश का गठन अधिसूचित कर दिया है, जो पिछले वर्श से चालू हो गये है। इन कोशों का सुदृढ़ किया जा रहा हैं

107. अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा भाुरू की गई ऋण विनियम योजना हमारे लिए बहुत लाभदायक रही हैं हमने

अब तक 13 प्रति ात और इससे ऊंची ब्याज दर वाले 1764 करोड़ रूपये के केन्द्रीय ऋणों का भुगतान किया है आगामी वर्श के दौरान 1320 करोड़ रूपये के कन्द्रीय ऋणों को चुकता करने का भी हमारा प्रस्ताव है। इस योजना से लगभग 190 करोड़ रूपये की ब्याज राहत मिलने की सम्भावना है।

108. उपरोक्त उपायों से हामरे वित्तीय प्रबन्धन में काफी सुधार हुआ है। राजस्व घाटा 1998–99 में सर्वाधिक 1540. 20 करोड़ रूपये से कम होकरवर्श 2002–03 में 685.11 करोड़ रूपये रह गया। सकल घरेलू उत्पाद प्रति ातता की दृश्टि से राजस्व घाटा 1998–99 में सर्वाधिक 3.5 प्रति ात से कम होकर वर्श 2002–03 में 1.04 प्रति ात रह गया। राजकोशीय घाटा वर्श 1998–99 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.1 प्रति ात से कम होकर वर्श 2002–03 में 2.23 प्रति ात से बढ़कर वर्श 2002–03 में 8.43 प्रति ात हो गया।

109. हमारे कुल वित्तीय प्रबन्धन की उल्लेखीनय वि ोशता यह है कि हरियाण देश का एकमात्र राज्य है। जिसने चालू वित्त वर्श के दौरानएक दिन के लिए भी ''ओवर ड्राफ्ट'' नही लिया। हमने विभिन्न माध्यमों से प्राप्त केन्द्रीय संसाधनों का भी सदुपयोग किया है ंयोजना आयोग, भारत सरकार ने हाल ही में एक समीक्षा बैठक में केन्द्रदीय धन का सदुपयोग करने के लिए राज्य की सराहना की है।

बजट अनुमान 2004–05

110. माननीय अध्यक्ष महोदय, मै अब इस गरिमामय सदन के सम्मुख वर्श 2004–05 के बजट अनुमार प्रस्तुत करता हूं।

111. वर्श 2002–03, भारतीय रिजर्व बैंक के खातों के अनुसार 454.16 करोड़ रूप्ये के घाटे के साथ आरम्भ हुआ और 226.98 करोड़ रूप्ये के घाटे के साथ समाप्त हुआ। अतः वर्श के दौरान बजट घाटे में 227.18 करोड़ रूपये के घाटे के साथ समाप्त हुआ। अतः वर्श के दौरान बजट घाटे में 227.18 करोड़ रूपये का सुधार हुआ। यह राज्य सरकार के विवेक ाील वित्तीय प्रबन्धन का सूचक है।

112. वित्त वर्श 2003–04, भारतीय रिजर्व बैंक के खातों के अनुसार, 226.98 करोड़ रूपये के घाटे के साथ आरम्भ हुआ और इसकी 339.58 करोउ़ रूपये के घाटे के साथ समाप्त होने की सम्भावना है। इस प्रकार, वर्श के दौरान बजट सम्बन्धी लेन–देन 112.60 करोड़ रूपये के घाटे को द ार्ाता है ओर बजट अनुमानों में 670.96 करोड़ रूपये के घाटे के मुकाबले 331.38 करोड़ रूपये के सुधार का सूचक है। यह राजकोशीय प्रबन्धन के समुचित विनियमन की दि ाा में हमारेद्वारा किये गये ठोस प्रयासों की बदौल्त सम्भव हो पाया है।

113. वित्त वर्श 2004–05, 339.58 करोड़ रूपये के घाटे के साथ आरम्भ होने और 438.97 करोड़ रूपये के घाटे के

साथ समाप्त होने की सम्भावना है। इस प्रकार, वर्श के दौरान हुआ लेन–देन 99.39 करोड़ रूप्ये के घाटे को द ार्शाता है। बजट अनुमानों में केन्द्र द्वारा आयोजित योजनाओं और अन्य विकास योजनाओं के लिए 524.77 करोड़ रूप्ये के परिव्यय के अतिरिक्त राज्य योजना के लिए 2175 करोड़ रूपये का प्रावधान है।

114. वर्श 2004–05 के बजट अनुमानों में राज्य के समेकित कोश में कुल प्राप्तियां 17410.86 करोड़ रूपये की दिखाई गई है, जबकि वर्श 2003–04 के सं ाोधित अनुमानों में ये 15150. 71 करोड़ रूपये की है। वर्श 2004–05 के सं ाोधित अनुमानों में यह 15596.66 करोड़ रूपये था।

115. वर्श 2004–05 के बजट अनुमानों में राजस्व प्राप्तियां बढ़कर 10791.40 करोड़ रूपये हो जाने की सम्भावना है, जबकि वर्श 2003–04 के सं ाोधित अनुमानों में ये 9769.36 करोड़ रूपये की थी। राजस्व प्राप्तियों में यह वृद्धि 1022.04 करोड़ रूपये अर्थात 10.5 प्रति ात है। वर्श 2004–05 के बजट अनुमानों में 11684.02 करोड़ रूपये का राजस्व खर्च अनुमानित है, जो वर्श 2003–04 के सं ाोधित अनुमान में 10673.51 करोड़ यपये के खर्च से 1010.51 करोड़ रूपये अधिक है। खर्च में यह वृद्धि 9.4 प्रति ात है ओर यह मुख्यतः ब्याज भुगतानमें 301.68 करोड़ रूपये, वेतन तथा पैं ान के भुगतान में 240.70 करोड़ रूपये और बिजली क्षेत्र को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में 92.38 करोड़ रूपये की बढ़ोतरी के कारण हुई है।

116. अध्यक्ष महोदय, राजस्व लेखा महत्वपूर्ण सुधार को द ार्शाता है वर्श 2002–03 के दौरान राजस्व घाटा सं ाोधित अनुमानों में 1086.43 करोड़ रूपये से कम हेागर 685.11 करोड़ रूपये रह गया है। राजस्व घाटा बजट अनुमानों में 920.28 करोड़ रूपये से कम होकर सं ाोधित अनुमानों में 904.15 करोड़ रूपये रह जाने की सम्भावना है। बजट अनुमान 2004–05 में इसके और कम होकर 892.62 करोड़ रूप्ये रह जाने की सम्भावना है।

117.अन्य उल्लखीनय बात यह है कि वर्श 2004–05 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में होने वाली 10.5 प्रतिशत की वृद्धि राजस्व खर्च में 9.4 प्रति ात वृद्धि से अधिक है, जो अच्छे वित्तीय प्रबन्धन का सूचक है। हमारी सरकार द्वारा भाुरू किये गये राजकोशीय उपायों से राजस्व घाटे में और कमी करने का हमारा प्रस्ताव है।

118. मै इस गरिमामय सदन को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार अपने नगारिकों, व्यापार व उद्योग के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। हम ऐसी प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए हमे ाा तैयार है, जो परे ाानी का कारण है। जैसाकि मै पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि हमारी सरकार ने कराधान की वैट प्रणाली अपनाई है। हमने इस प्रणाली के अन्तर्गत वैट विक्रेताओं को विभिन्न रियायतें दी है। विक्रेताओं का एकमु त कर भुगतान का विकल्प दिया गया है। रासायनिक उर्वरकों, बायोगैस संयंत्र, बर्नर और हॉट प्लेट इत्यादि जैसी विभिन्न वस्तुओं को कर से छूट

दी गई हैं जैविक खादों, जिप्सम, पुरानी कारों, टायरों और टयूबों, बिजली के सामान इत्यादि पर कर की दर में कमी की गई है। वि ोश आर्थिक जोन निर्योतोन्मुखी यूनिटों, निर्यात प्रोसैसिंग जोन, निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क, इत्यादि के अन्तर्गत स्थापित यूनिटों द्वारा की जाने वाली बिक्री पर कर–दर भून्य है। हमें आ ाा है। कि इन उपायों और रियायतों से व्यापारी समुदाय करों का भुगतान ईमानदारी से करेगा।

119. अध्यक्ष महोदय, प्रभावी एवं प्रतिबद्ध भाासन के लिए सरकारी कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वर्तमान सरकार कर्मचारियों के कल्याण के प्रति पूर्णतःसजग हैं हरियाणा सरकार का पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की उस सिफारि ा को भी 01.04.2004 से सैद्धान्तिक तौर परस्पीकार करने का प्रस्ताव है, जिसमें आयोग ने कहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पिछले वेतन आयोग द्वारा प्रयोग किये गए मूल सूचकांक से 50 प्रति ात से बढ़ जाने पर महंगाई भत्ते को महंगाई वेतन में परिवर्तित कर दिया जाए औरऐसे महंगाई भत्ते को महांगई वेतन माना जाए और इसकी सेवा निवृति लाभों समेत सभी उद्दे य के लिए गणना की जाये। भारत सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी किये जाने पर हरियाणा सरकार द्वारा भी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इससे सरकारी खजाने पर लगभग 115 करोड़ रूपये का वित्तीय भार पड़ने की संम्भावना है।

120. माननीय सदस्यगण, इस बात की प्र ांसा करेगे कि बजट घाटा ब्रबन्धीनय सीमा में है तथा प्रस्तावित उपायों से घाटे में और कमी आयेगी। हमें आ ाा है कि आगामी वर्श में राश्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार के परिणामस्वरूप केन्द्रीय करों तथा केन्द्र से मिलने वाली अन्य सहायता में वृद्धि करने की बजाय लोगों के सहयोग से कर नियमों के निश्पक्ष व प्रभावी क्रियान्वयन के द्वारा ज्यादा राजस्व जुटाना है। इसलिए बजट में नया कर लागने का कोई प्रसताव नही है। मुझे पूरा वि वास है कि हम माननीय सदस्यों तथा हरियाणा के लोगों के सहयोग व सहायता से अपने सभी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम होगें।

121. इस भाशण को समाप्त करने सेपहले मैं वित्त विभाग एवं एन आई सी के अधिकारियेां एवं कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होने अथक परिश्रम करके इन बजट प्रस्तावों को तैयार करने में मरी सहायता की है।

122. महोदय, अब मै वर्श 2004–05 के बजट अनुमानों को इन गरिमामय सदन के विचार तथा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूं।

Mr. Speakaer: Now, the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorro, the 13the February, 2004

11.34 Hrs

(The Sabha then adjourned till 9-30 A.M. on Friday, the 13the February, 2004)